RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 03, अंक 4 मासिक पत्रिका
25 अप्रैल 2024

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

घटता-बढ़ता रहता है मतदान, दंड न मानें

पढ़िए... पेज 9

जम्मू-कश्मीर को फिर मिलेगा राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विस चुनाव : पीएम

पढ़िए... पेज 19

मध्य प्रदेश में अब निजी स्कूलों की मनमानी पर कसेगी नकेल...

हमारा देश हमारा अभिमान
परिवार की ओर से चैत्र नवरात्र
एवं रामनवमी पर्व की

हार्दिक शुभकामनाएं

हमारा देश
हमाराअभिमान

25 अप्रैल 2024

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडो कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	.....	02
शुभाशीष	.....	03
कवर स्टोरी	.....	04-05
देश	.....	06-07
विदेश	.....	08
देश	.....	09
राजस्थान	.....	10
पश्चिम बंगाल	.....	11
देश	.....	12
सर्वे	.....	13
देश	.....	14-15
वित्त	.....	16
राजनीति	.....	17
प्रदेश	.....	20-21
साइबर	.....	22
देश	.....	23
मध्यप्रदेश	.....	24
राजस्थान	.....	25
प्रदेश	.....	31
प्रदेश	.....	26-27
इन्दौर	.....	34-35
इन्दौर	.....	36-37
स्वास्थ्य	.....	38-39
पर्यटन	.....	40-41
धर्म	.....	42-43
धर्म	.....	44-45
लाइफ स्टाइल	.....	49
ग्लैमर	.....	50

48

महिला प्रधान फिल्मों पर भी पैसा लगाने की जरूरत है

संपादकीय

नहीं डालेंगे अपना वोट तो सरकार से कैसे कर सकेंगे सवाल?

पहले चरण के मतदान के दौरान देश के कई हिस्सों में कई मतदान केन्द्रों पर मतदान का बहिष्कार के समाचार भी देखने सुनने को मिले। यह भी अपने आप में सही विकल्प नहीं कहा जा सकता। आखिर मतदान का बहिष्कार कर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। 18 वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रेल को देश के 13 राज्यों के 89 लोकसभा सीटों के लिए होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान 2019 की तुलना में कम हुआ है। यह अपने आप में चिंतनीय हो जाता है। मतदान कम होने के कारणों का विश्लेषण करने का ना तो यह सही समय है और ना ही यह विश्लेषण का समय है कि मतदान कम होने से किसे लाभ होगा या किसे हानि होगी। लाभहानि का आकलन करना राजनीतिक दलों का विषय हो सकता है। पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों द्वारा मताधिकार का उपयोग नहीं करना अपने आप में गंभीर हो जाता है। एक और हम निर्वाचित सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं और रखनी भी चाहिए वहीं हम अपनी सरकार चुनने के लिए घर से मतदान करने के लिए भी निकलना अपनी तोहिन समझने लगते हैं। आखिर इतनी गैर जिम्मेदार नागरिक हम कैसे हो सकते हैं? यहां पर बरबस देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी पर ध्यान चला जाता है कि जब हम मतदान के दायित्व को पूरा नहीं कर सकते तो फिर चुनी हुई सरकार से सवाल करने या उससे किसी तरह की अपेक्षा रखने का हक भी हमें नहीं होना चाहिए। एक एनजीओ के द्वारा दायर पीएल को इसी भावार्थ के साथ खारिज कर दिया गया था। वैसे भी हमारा दायित्व हो जाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम थोड़ा सा समय निकाल कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पांच साल में एक बार मिलने वाले अवसर को नकारात्मक सोच या गैरजिम्मेदारी से खो देना किसी भी हालात में उचित नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र के महायज्ञ में प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग कर मतदान करके अपनी आहुति देने का अवसर मिलता है।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

हम श्रीराम तो बनना चाहते हैं पर श्रीराम के आदर्शों को अपनाना नहीं चाहते

श्री राम के चौदह वर्ष के वनवास से हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। जन्म, बचपन, शासन एवं मृत्यु तक उनका सम्पूर्ण जीवन प्रकृति-प्रेम एवं पर्यावरण चेतना से ओतप्रोत है। आज देश एवं दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान श्रीराम के प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण की शिक्षाओं से मिलता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के रामनवमी बहुत ही शुभ दिन होता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि त्रेता युग में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्रीराम का अवतरण हुआ था। धार्मिक मत है कि सभी प्रकार के मांगलिक कार्य इस दिन बिना मुहूर्त विचार किये भी संपन्न किए जा सकते हैं। रामनवमी पर पारिवारिक सुख-शांति और समृद्धि के लिए व्रत भी रखा जाता है। भगवान श्रीराम की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। साथ ही साधक भगवान श्रीराम की कृपा के भागी बनते हैं। पर्यावरण की विकराल होती समस्या के संदर्भ में भगवान श्रीराम का प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संदेश इस समस्या के समाधान का एक बड़ा माध्यम बन सकता है, ऐसा हुआ तो हमारा रामनवमी मनाना सार्थक होगा। श्रीराम के चौदह वर्ष के वनवास से हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। जन्म, बचपन, शासन एवं मृत्यु तक उनका सम्पूर्ण जीवन प्रकृति-प्रेम एवं पर्यावरण चेतना से ओतप्रोत है। आज देश एवं दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान श्रीराम के प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण की शिक्षाओं से मिलता है। भारतीय संस्कृति में हरे-भरे पेड़, पवित्र नदियां, पहाड़, झरनों, पशु-पक्षियों की रक्षा करने का संदेश हमें विरासत में मिला है। स्वयं भगवान श्रीराम व माता सीता 14 वर्षों तक वन में रहकर प्रकृति को प्रदूषण से बचाने का संदेश दिया। ऋषि-मुनियों के हवन-यज्ञ के जरिए निकलने वाले ऑक्सीजन को अवरोध पहुंचाने वाले दैत्यों का वध करके प्रकृति की रक्षा की। जब श्रीराम ने हमें प्रकृति के साथ जुड़कर रहने का संदेश दिया है तो हम वर्तमान में क्यों प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

घटता-बढ़ता रहता है मतदान, ट्रेंड न मानें

करीब डेढ़ दशक पहले मतदान घटने का अर्थ सत्तारूढ़ घटक की विजय तथा मतदान बढ़ने का अर्थ पराजय के रूप में लिया जाता था और प्राय: ऐसा देखा भी गया। किंतु 2010 के बाद यह प्रवृत्ति बदली है। मतदान बढ़ने के बावजूद सरकारें वापस सत्ता में आई हैं और मतदान घटने के बावजूद गई भी हैं। इसलिए इस आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न होने को लेकर कई तरह के आकलन सामने आ रहे हैं। पहले चरण में नौ राज्यों तथा तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो चुका है। माना जा रहा था कि देश के एक बड़े हिस्से में मतदान संपन्न होने के बाद इसकी प्रवृत्तियों का आकलन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन मतदान के बाद आम टिप्पणी यही है कि मतदान प्रवृत्तियों का आकलन आसान होने के बजाय कठिन हुआ है। बहरहाल, पहले चरण के मतदान की सबसे बड़ी विशेषता रही कि पश्चिम बंगाल और मणिपुर को छोड़कर कहीं भी हिंसा की घटना नहीं हुई। किसी बड़ी घटना का न होना बताता है कि हमारे देश का चुनाव तंत्र बिल्कुल सहज, सामान्य और सुव्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि हम कम अवधि और कम चरणों में भी लोकसभा चुनाव को पूरा

कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर हो रही है और इस बारे में कई तरह के आकलन किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा गिरा है। इनमें भी सभी जगह मतदान एक समान भी नहीं रहे। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ज्यादा मतदान हुए, तो बिहार और उत्तराखंड में अत्यंत कम। इन दोनों राज्यों में भी अलग-अलग क्षेत्र को देखें, तो कहीं ज्यादा, तो कहीं कम मतदान हुआ है।

यह साफ है कि एकाध स्थानों को छोड़कर ज्यादातर जगहों में मतदान प्रतिशत गिरा है। उत्तर प्रदेश में 2019 के मुकाबले लगभग 5.30 प्रतिशत कम मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, यह करीब 68.29 प्रतिशत है। यानी करीब 1.14 फीसदी कम मतदान हुआ है, तो कहा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत में ज्यादा गिरावट नहीं है। नगालैंड में मतदान प्रतिशत इसलिए ज्यादा गिरा, क्योंकि वहां के छह जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया। ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स फ्रंट ने अलग राज्य की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। इसे हम मतदान में कमी की प्रवृति नहीं मान सकते।

करीब डेढ़ दशक पहले मतदान घटने का अर्थ सत्तारूढ़ घटक की विजय तथा मतदान बढ़ने का अर्थ पराजय के रूप में लिया जाता था और प्रायः ऐसा देखा भी गया। किंतु 2010 के बाद यह प्रवृत्ति बदली है। मतदान बढ़ने के बावजूद सरकारें वापस सत्ता में आई हैं और मतदान घटने के बावजूद गई भी हैं। इसलिए इस आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दूसरे, हर जगह मतदान प्रतिशत ज्यादा गिरा भी नहीं है। तीसरे, बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्षों के मतदाताओं में एक-दूसरे को हराने और जिताने के लिए प्रखर प्रतिस्पर्धा है।

सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत का घटना सामान्य नहीं है। इस क्षेत्र में जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है। ऐसे में यह आकलन करना कठिन है कि जहां मतदान प्रतिशत गिरा, वहां किस पक्ष या पार्टी के मतदाता नहीं आए। अगर भाजपा विरोधी उसे हराना चाहते थे, तो उन्हें भारी संख्या में निकलना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि सपा के कोर मतदाता यानी मुसलमान और यादवों का बड़ा समूह आक्रामक होकर मतदान कर रहा था। विरोधी भारी संख्या में निकलेंगे, तो समर्थक भी इसका ध्यान रखेंगे।

हालांकि उम्मीदवारों के चयन, दूसरे दलों से आए लोगों को महत्व मिलने तथा कहीं-कहीं गठबंधन को लेकर भाजपा समर्थकों व कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष है तथा एक जाति विशेष ने भी विरोधात्मक रूप अख्तियार किया था। बावजूद इसके यह कहना कठिन होगा कि भाजपा समर्थक मतदाता ही ज्यादा संख्या में मतदान करने नहीं निकले।

अभी तक के चुनाव अभियान में जनता की उदासीनता दिखी है। हालांकि विपक्ष के प्रचार के विपरीत प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को लेकर आम जनता में व्यापक आक्रोश नहीं दिखा है। कल्याण कार्यक्रमों के लाभार्थी तथा विकास नीति की प्रशंसा करने वाले हर जगह दिखाई देते हैं। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा से लेकर समान नागरिक संहिता एवं नागरिकता संशोधन कानून आदि पर विपक्ष के रवैये ने भाजपा समर्थकों में प्रतिक्रिया भी पैदा की है। असंतुष्ट लोगों में भी यह भाव है कि अगर यह सरकार हार गई, तो कहा जाएगा कि हिंदुत्व विचारधारा की हार हो गई है। जिस जाति के विद्रोह की चर्चा हो रही है, वे भी भाजपा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने भाजपा के विरोध में मतदान किया होगा।

हृदय प्रदेश के मसले : चुनाव 2024 और हिंदी प्रदेश...

अक्सर हिंदी पट्टी ही यह तय करती है कि दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा। छह राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो इस इलाके के मूल हिस्सा हैं, की 189 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों के लिए पहले दो चरणों में वोट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान - जहां भाजपा ने पिछले साल विधानसभा चुनाव जीते थे - में दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बीच सीधा मुकाबला है, जो यह निर्धारित कर सकता है कि अगली सरकार की कमान किसे मिलेगी। भाजपा की तरफ से, इस आम चुनाव की जोरदार शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 मार्च को चुनाव अधिसूचना से पहले ही पार्टी और उसके सहयोगियों के लिए 400 सीटों की जीत का लक्ष्य रखा था। उसके अगले ही दिन, उन्होंने कैबिनेट से अगली सरकार, जिसके गठन को लेकर उन्हें पूरा भरोसा है, के पहले 100 दिनों की योजना का मसौदा तैयार करने के लिए भी कहा। दूसरी तरफ, विपक्ष ने अपना अभियान अपेक्षाकृत कमजोर और बेहद कम उत्साह की स्थिति से शुरू किया। इंडिया ब्लॉक के घटक अभी भी सीट-बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर आपस में ही भिड़े हुए थे। तब से अब तक हुए विभिन्न घटनाक्रमों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों का खुलासा और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, दो ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने विपक्ष के कम महत्वपूर्ण अभियान में ऊर्जा भर दी और आर्थिक गिरावट, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उजागर किया।

भाजपा राष्ट्रवाद और हिंदू एकजुटता का कहीं ज्यादा तीखा नारा लगाकर इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। वह विपक्ष को 'सनातन धर्म विरोधी' करार दे रही है और कांग्रेस पर निशाना साध रही है और उसके घोषणापत्र को "मुस्लिम लीग की छाप" करार दे रही है। '400-पार' के नारे को लेकर

हिन्दुओं के निचले तबके के बीच छाए एक स्पष्ट डर ने अब भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है। भाजपा नेताओं के इस आशय के बयानों कि भारी बहुमत उन्हें संविधान को फिर से लिखने में समर्थ बनायेगा, को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित और आदिवासी समुदायों द्वारा एक खतरे के रूप में देखा गया है। पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों में, जिसमें उन्होंने मतदाताओं को यह आश्वासन दिया कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, भाजपा ने अपने कानों से इस डर को सुना। भाजपा का प्रचार अभियान इस बात को समझाने पर केंद्रित है कि उसकी तरफ से जातिगत आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। और वह कांग्रेस पर मुसलमानों के लिए आरक्षण की योजना बनाने का आरोप लगा रही है। हिंदी पट्टी में, जहां जाति और सांप्रदायिक पहचान एक जटिल अंतरसंबंध में गुथे हैं, भाजपा की सफलता जाति पर हावी होने वाली धार्मिक लामबंदी से निर्धारित होती है। आर्थिक और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाली नीतियों का कांग्रेस का वादा भी चुनाव अभियान के केंद्र में है। कांग्रेस की उम्मीद जहां गरीबों और निम्नवर्गीय जातियों को एकजुट करने की है, वहीं भाजपा समाजवादी तानाशाही का डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। उसके द्वारा धन के पुनर्वितरण का डर दिखाकर देश के सबसे गरीब लोगों को संबोधित किया जाना, इस हिंदी पट्टी का एक खास विस्मयकारी विरोधाभास है।

क्या है केसीसी कर्ज स्कीम...

..इस साल कितने किसानों को सरकार देगी ये ऋण

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 1998 में की है। इसका फायदा भारत का कोई भी किसान ले सकता है। इस कर्ज स्कीम का उद्देश्य कम ब्याज दर में किसानों को लोन उपलब्ध कराना है। इसमें किसान 3 लाख रुपए तक का लोन चार प्रतिशत ब्याज पर ले सकते हैं। किसानों को खेती- किसानी के लिए हमेशा पैसों को जरूरत रहती है। किसान को फसल लगाने, उसमें खाद पानी देने और इसके देखभाल के लिए कहीं ना कहीं से पैसो का इंतजाम करना पड़ता है। कई बार तो किसान मोटे ब्याज पर साहूकार और बैंक से कर्ज भी लेते हैं। ऐसे में किसान फसल नहीं होने या सही उपज नहीं होने पर कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। सरकार ने किसानो के फायदे के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की इस योजना में जमीन को गिरवी रखकर बहुत कम ब्याज पर किसान खेती किसानी के लिए कर्ज ले सकते हैं। किसानों के लिए सरकार द्वारा लाई गई इस लोन योजना को किसान क्रेडिट कार्ड या ग्रीन कार्ड कहा जाता है।

1998 में इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के साथ मिलकर की है। इस योजना के तहत किसान अपने नजदीकी बैंक जाकर अपने जमीन के कागजात जमा कर और लोन लेने की सामान्य कागजी औपचारिकताएं पूरी कर कर्ज ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार किसानों को मात्र 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है। हालाकि इसके लिए कुछ शर्त होते हैं जिसका पालन करना होता है।

केसीसी लोन योजना के बारे में जानकारी...

इस योजना का नाम-किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। इसे केंद्र सरकार ने साल 1998 में प्रारंभ किया है। इसका फायदा भारत का कोई भी किसान ले सकता है। इस कर्ज स्कीम का उद्देश्य कम ब्याज दर में किसानों को लोन उपलब्ध कराना है। इसमें किसान 3 लाख रुपए तक का लोन चार प्रतिशत ब्याज पर ले सकते हैं। अगर किसान इससे ज्यादा लोन लेते हैं तो ब्याज दर बढ़ जाता है।

किसानों को कितना ब्याज देना होता है?

किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% की ब्याज दर होता है। इस योजना में 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यदि आप एक साल पूरा होने से पहले ही लोन चुका देते हैं तो किसानों को 3 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इस तरह इस लोन का ब्याज दर महज चार प्रतिशत रह जाता है। इसलिए इसे देश का सबसे सस्ता लोन कहा जाता है, जो भारत के किसानों को मिलता है।

90 हजार किसानों को लोन देने का लक्ष्य

बिहार के सहकारी बैंकों की तरफ से 2024-25 में 90 हजार किसानों को कृषि लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल से 10 हजार अधिक किसानों में केसीसी लोन वितरण करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इन किसानों में 270 करोड़ रुपए लोन के तौर पर बांटे जाएंगे। पिछले साल 80 हजार किसानों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया था।इसके साथ ही अगले तीन सालों तक हर साल 10 हजार किसानों की संख्या लोन के लिए बढ़ाने की योजना है। 2027-28 तक पांच लाख किसानों को केसीसी लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। 2025-26 में एक लाख किसानों 300 करोड़ रुपए लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में दो लाख किसानों के सहकारी लोन का 90% ब्याज माफ करने की बात कही थी।

शुरू से सनातन विरोधी रही है कांग्रेस, भगवान राम को बताया था काल्पनिक

जे पी नड्डा ने आपने 2014 में मोदी जी को चुनाव जिताया। जो भारत देश पिछड़ रहा था, वो 5 साल के अंदर दुनिया के अग्रणी देशों में आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि 1947 में देश विभाजन के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में काफी लोगों को धार्मिक रूप से प्रताड़ित करके वहां से निकाला गया था।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लोरमी शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए, नड्डा ने पिछले 10 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। नड्डा ने कहा कि मैं आप सबको सबसे पहले हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि 3 महीने पहले, मैं विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए यहां आया था और आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के निवेदन को सुना-समझा। और आपने बघेल की कुशासित सरकार को उखाड़ फेंका और भाजपा की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि चुनाव में आपके वोट का बहुत महत्व है, आपका वोट बहुत बड़े-बड़े कार्य कराता है और बड़े-बड़े फैसले लेने की ताकत रखता है।

जेपी नड्डा ने आपने 2014 में मोदी जी को चुनाव जिताया। जो भारत देश पिछड़ रहा था, वो 5 साल के अंदर दुनिया के अग्रणी देशों में आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि 1947 में देश विभाजन के बाद

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में काफी लोगों को धार्मिक रूप से प्रताड़ित करके वहां से निकाला गया था। उनको नागरिकता देने की बात तो सभी करते थे, लेकिन नागरिकता देने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि सभी तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति में डूबे हुए थे।

उन्होंने कहा कि मोदी जी को आपने ताकत दी, उन्होंने CAA लागू किया और जो लोग भारत में आए थे, उन्हें नागरिकता देने का काम किया गया। उन्हों कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार गरीब, गांव, वंचित, दलित, महिला सशक्तिकरण, किसान और युवाओं के लिए समर्पित है। आज गांवों का सर्वांगीण विकास हुआ है। नड्डा ने कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ पक्के घर बनकर तैयार हुए हैं। ये मकान सभी सुविधाओं से युक्त हैं। आप एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और हम 5 साल में 3 करोड़ घर और बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव राम विरोधी और सनातन विरोधी रही है। UPA की मनमोहन सिंह सरकार के समय, इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है और उनका कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। अब न्यास ने उनको मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया।

श्रीराम का निमंत्रण ठुकराने वालों को जनता ठुकराएगी : इन्दौर सांसद

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक पाँच के चार वार्डो में कल शाम को भाजपा प्रत्याक्षी सांसद शंकर लालवानी सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। पार्षद व एम.आई.सी.मेंबर राजेश उदावत,विधानसभा क्षेत्र क्रमांक पाँच के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र महाजन ने बताया की सरदार वल्लभ भाई पटेल मण्डल के चार वार्ड 41,48,49 और 50 में कार्यकतार्ओं का सम्मेलन हुआ।वार्ड क्रमांक 49 का सम्मेलन रात 9 बजे तिलक नगर एक्सटेंसन में इंडो किड्स स्कूल में हुआ। भाजपा लोकसभा प्रत्याक्षी सांसद शंकर लालवानी ने कार्यकतार्ओं को संबोधित करते हुए कहा कि सौगंध राम की खाते है,मंदिर वहीं बनाएँगेङ्घतो कांग्रेसी कहते थे,तारीख नहीं बताएँगे।आयोध्या में श्रीराम मंदिर आंदोलन का कारसेवक हूँ।रामजन्मभूमि के लिए बहुत संघर्ष हुआ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से 500 वर्षों बाद आयोध्या में श्रीराम मंदिर बना है।जिसके निमंत्रण को कांग्रेसियों ने ठुकराया।उन कॉग्रेसीयो को

जनता इस चुनाव में ठुकराएगी। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा मोदी सरकार आने के बाद जो हथियार हम आयात किया करते थे,वो आज हम निर्यात कर रहे है।आतंकवाद के साथ नक्सलवाद को भी खत्म किया है।भारत व यहाँ के नागरिकों को विश्व में उचित सम्मान मिल रहा है। डॉ निशांत खरे ने प्रदेश में पहले चरण में कम मतदान पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक मतदान के लिए कार्यकतार्ओं को मेहनत करने की बात कही। पार्षद व एम.आई.सी.मेंबर राजेश उदावत,विधानसभा क्षेत्र क्रमांक पाँच के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र महाजन ने बताया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशहित कार्यों से प्रभावित होकर वार्ड क्रमांक 49 के 51 कॉग्रेसी कार्यकतार्ओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर केसरिया दुपटा पहनकर कॉग्रेस को अधिक से अधिक वोट से हराने का संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व पार्षद परसराम वर्मा,अनुराधा उदावत,अजय नरूका,आशा होलासराय सोनी, रमेश भारद्वाज, दीपेश पालीविया, मधुसूधन शर्मा, दिलीप पाटनी, पप्पी शर्मा, अशोक डागी, तीरथपाल यादव,पवन भार्गव,राकेश जैन,कन्हिया जोशी, राजा कोठारी, राजेंद्र महाजन, रोमिल सोनी,अभिषेक सोनी, पंकज चौहान, चद्रशेखर वर्मा, जनार्दन शर्मा आदि मोजूद थे।

कचरा एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, जीवनशैली में लाना होगा बदलाव

संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर आज यानी 30 मार्च को पूरी दुनिया में शून्य कचरा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। विश्व के बहुत से देशों ने कचरे से निजात पाने का संकल्प लिया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि कचरे की मात्रा कम होने के बजाय निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि वर्तमान में उत्पन्न कचरे की मात्रा का आकलन किया जाए, तो वह इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की 25 परिधि बन जाए या चंद्रमा तक आने-जाने का सफर पूरा हो जाए। कचरे के पैदा होने और कुप्रबंधन से जल, थल और नभ प्रदूषित होते हैं, नतीजतन मानव सभ्यता पर इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई कदम उठाए गए। लेकिन प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन की दर में वृद्धि ही हुई है। वर्तमान संदर्भ में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण की दर विगत 10 वर्षों में बढ़ी है, लेकिन अब भी बड़ी आबादी, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कचरा प्रबंधन की गतिविधियों से कोसों दूर हैं।

सुदूर ग्रामीण इलाकों तक उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के कारण प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन दर में कई गुना वृद्धि हुई है। पहले यह माना जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर ही कचरे का निस्तारण हो जाता है, क्योंकि उसमें अधिकांश भाग जैविक कचरे का होता था। लेकिन अब प्लास्टिक, कागज, पैकेजिंग इत्यादि ने आम ग्रामीणों के जीवन में जगह बना ली है, जिससे कचरे की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। अगले कुछ वर्षों में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले देश में कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यदि कचरा उत्पादन की यही गति जारी रही, तो वर्ष 2050 तक नियंत्रित एवं अनियंत्रित कचरे की मात्रा वर्ष 2020 की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो जाएगी और उसके निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना मुश्किल होगा, जिससे आबादी बुरी तरह प्रभावित होगी। कचरे की बढ़ी हुई मात्रा के निस्तारण के लिए भूमि संसाधन भी अपर्याप्त होंगे। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है कि प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन को कम किया जाए। दुर्भाग्यवश अभी तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। वर्तमान प्रयास कचरा संग्रहण, पृथक्कीकरण एवं निस्तारण तक ही सीमित हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद लगभग दो तिहाई कचरे का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण नहीं हो पाता है। खुले में कचरा फेंक देने से जहां प्रदूषण एवं बीमारियां बढ़ने का डर रहता है, वहीं कचरे में आग लगने की घटनाएं भी देखी जाती हैं।

न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 2 जून से ही

न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर बार और बेंच के बीच एक बार फिर तकरार की स्थिति निर्मित हो गई है। न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 2 जून से शुरू होकर 30 जून तक रहेगा। हाई कोर्ट जबलपुर से इसके आदेश जारी भी हो गए हैं। इधर अधिवक्ता मांग कर रहे हैं कि न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह 13 मई से 15 जून तक रखा जाए।

इंदौर अभिभाषक संघ ने तो साधारण सभा बुलाकर सर्वानुमति से इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित कर जबलपुर भेज दिया है। हालांकि इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं आया है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि फिलहाल तो न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 2 जून से ही शुरू होगा। गौरतलब है कि न्यायालयों में वर्षों पुरानी परंपरा के मुताबिक 13 मई के आसपास एक माह के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता था। इस दौरान आपराधिक प्रकरणों के अलावा सिर्फ अर्जेन्ट मामले ही सुने जाते थे। सिविल मामलों की नियमित सुनवाई पूरी तरह से बंद रहती है। हालांकि आपराधिक प्रकरण भी इक्का-दुक्का ही सुनवाई के लिए लगते थे।

हाई और जिला कोर्ट में 2 से 30 जून तक अवकाश

हाई कोर्ट ने इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में आंशिक रूप से बदलाव किया है। हाई कोर्ट में 2 जून से 30 जून तक और जिला न्यायालयों में पहले की तरह 13 मई से 15 जून तक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अधिवक्ताओं ने मांग की कि दोनों न्यायालयों में एक जैसा अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि अलग-अलग अवकाश की तिथियां होने से अधिवक्ता अवकाश का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। इस पर हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय में अवकाश की तिथि में बदलाव करते हुए इसे भी 2 जून से 30 जून कर दिया।

बदलाव चाहते हैं वकील

इधर, अधिवक्ताओं का कहना है कि सर्वाधिक गर्मी तो मई माह में रहती है इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश भी मई में ही रहना चाहिए। जून में वर्षाकाल शुरू हो जाता है और बच्चों के स्कूल भी खुलने लगते हैं। ऐसे में अधिवक्ता चाहकर भी ग्रीष्मकालीन अवकाश में परिवार के साथ घूमने नहीं जा सकते। अधिवक्ताओं की मांग है कि अवकाश की तारीखों में बदलाव किया जाए और इसे पहले की तरह मई के दूसरे और जून के पहले पखवाड़े में रखा जाए। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय जबलपुर से ही हो सकेगा।

जम्मू-कश्मीर को फिर मिलेगा राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विस चुनाव : पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर उधमपुर रैली में जम्मू, कश्मीनर को फिर से राज्य का दर्जा देने की बात कही है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जम्मूर कश्मीर में जल्दक विधानसभा चुनाव होंगे। उन्हों ने कहा कि आप अपने सपने साझा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहां के चप्पे-चप्पे पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है- फिर एक बार मोदी सरकार। साथ ही पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 10 साल के अंदर पूरी तरह से बदल चुका है।

पीएम मोदी ने उधमपुर में कहा, 'जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे, वह समय दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इसे वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक-मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे।' पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दशकों बाद यह पहला चुनाव है, जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, सीमा पार से गोलीबारी जैसे मुद्दे नहीं हैं। उन्होंकने कहा कि माता वैष्णो देवी यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हों इसको लेकर पहले चिंता होती थी। आज स्थिति बदल गई है। आज यहां विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। यहां चप्पे-चप्पे पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है- फिर एक बार मोदी सरकार।

आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा कसा : पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 10 साल के अंदर पूरी तरह बदल चुका है। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर का मन बदला है। निराशा से आशा की ओर बढ़े हैं, जीवन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ है। 10 साल में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत कसा है। अब आने 5 सालों में इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। भाजपा के नेतृत्वअ वाली केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था।

जो कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस ने उन्हें विश्वासघाती बताया...

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से कांग्रेस के एक पूर्व विधायक और पार्टी के कई अन्य स्थानीय नेता शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। इस पर कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने उन्हें विश्वासघाती बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की छह लोकसभा सीट पर मतदान के एक दिन बाद यहां एक कार्यक्रम में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हरिवल्लभ शुक्ला और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं का भाजपा में स्वागत किया।

यादव ने भाजपा के नए सदस्यों से कहा, "हम पार्टी में आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। हम एकमत होकर काम करने जा रहे हैं। आप सुझाव देने और पार्टी (भाजपा) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वतंत्र हैं। भाजपा की एक विज्ञप्ति में दावा किया गया कि समारोह में 100 से अधिक कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में करने के लिए एक अभियान चलाया है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का परिवार मध्य प्रदेश में सबसे तेज

गति से विस्तार कर रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार के के मिश्रा ने शुक्ला को एक चुकी हुई ताकत बताया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व विधायक के जाने से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, "जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं वे अपनी राजनीतिक मां को धोखा दे रहे हैं। उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन जब पार्टी को वापस देने और विभाजनकारी ताकतों से लड़ने का समय आया, तो उन्होंने अपनी पीठ दिखा दी और धन और बाहुबल के प्रलोभन में भाग गए। मिश्रा ने कहा, इतिहास इन विश्वासघातियों को माफ नहीं करेगा।

यूपी-बिहार को दिया ये आदेश...

गेहूं को लेकर सरकार का प्लान, 48 घंटों में मिलेगा एमएसपी का पैसा...

लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सरकार ने किसानों और आम जनता को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे गैर-पारंपरिक राज्यों को गेहूं खरीद में इजाफा करने का ऐलान किया है। चालू विपणन वर्ष 2024-25 में सरकार ने इस खरीद को सात गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है।

इन तीन राज्यों ने 2023-24 विपणन वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल में सिर्फ 6।7 लाख टन का योगदान दिया था। वहीं, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 प्रतिशत इनसे खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कितनी है गेहूं की MSP?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद आमतौर पर केंद्र की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। हालांकि, सहकारी समितियां नेफेड और एनसीसीएफ को भी इस साल पांच-पांच लाख टन के खरीद लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है। चालू वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।

यूपी-बिहार दे रहे बहुत कम योगदान : खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान अपनी क्षमता से बहुत कम का योगदान दे रहे हैं। हम इस साल कुल 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रख रहे हैं, जिसमें से हम तीन गैर-पारंपरिक खरीद वाले राज्यों से अकेले कम से कम 50 लाख टन खरीद की उम्मीद कर रहे हैं।

चुनाव का नहीं होगा असर

अक्टूबर से केंद्र इन तीन राज्यों के साथ खरीद स्तर बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कमियों को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इससे तीन राज्यों में खरीद के लेवल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सचिव ने कहा कि 2024 के आम चुनावों से गेहूं खरीद कार्यों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है।

उन्होंने कहा कि गैर-पारंपरिक राज्यों से गेहूं खरीद में ग्रोथ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत गेहूं के आवंटन को बहाल करने में मदद मिलेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि सचिव ने कहा कि सरकार ने 48 घंटों के भीतर किसानों के बैंक खातों में एमएसपी ट्रांसफर सुनिश्चित करने, किसानों के लिए खरीद के आकस्मिक बोझ को सुव्यवस्थित करने, बैंक खातों के साथ आधार एकीकरण जैसे बैंकिंग से संबंधित मुद्दों को सुचारू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रोडक्शन हॉटस्पॉट को लक्षित करते हुए अधिक खरीद केंद्र भी खोले हैं और मोबाइल खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों का लाभ उठाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने किसानों को 48 घंटे के भीतर एमएसपी का पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों को वर्किंग कैपिटल के माध्यम से संस्थागत तैयारी सुनिश्चित की है। सचिव ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों के बीच खरीद की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए दिल्ली में एफसीआई मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

7.06 लाख टन गेहूं बिका

गेहूं और चावल की कीमतों पर सचिव ने कहा कि 'भारत' ब्रांड गेहूं के आटे की खुदरा बिक्री शुरू होने के बाद आटे और गेहूं की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। अबतक करीब 7।06 लाख टन गेहूं का आटा बेचा जा चुका है। यहां तक कि चावल की खुदरा महंगाई दर भी पिछले दो महीने से 13 प्रतिशत और 14 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि फरवरी से अबतक भारत ब्रांड के तहत लगभग 3।1 लाख टन एफसीआई चावल बेचा जा चुका है।

चुनाव में कहीं बढ़ न जाएं प्याज का रेट, सरकार ने राहत देने का किया इंतजाम, किसान भी खुश...

सरकार ने प्याज की कीमत पर लगाम लगाने और किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए बफर स्टॉक में इजाफा करने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से जल्द 5 लाख टन प्याज की खरीद की जाएगी। प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदी अभी जारी रहेगी।

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की नजर चीजों के बढ़ते हुए दामों पर है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर आम आदमी से जुड़ी किसी भी चीज के रेट में बढ़ोतरी नहीं हो। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता करने के साथ ही पेट्रोल-डीजल के दाम में भी कटौती की गई थी। अब सरकार प्याज की बढ़ी कीमत को कम करने और बाजार को स्थिर रखने के लिए पांच लाख टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। पिछले साल के इस समय के मुकाबले इस साल थोक रेट में भी उछाल आया है। इससे ग्राहकों पर पहले के मुकाबले आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह कदम उठाया है।

निर्यात पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगाई गई थी

लेकिन पिछले दिनों सरकार ने अगले आदेश तक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इससे पहले प्याज निर्यात पर रोक 31 मार्च तक के लिए लगाई गई थी। इसके बाद प्याज की कीमत में संभावित गिरावट की चिंता के बीच सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह उनके फायदे को ध्यान में रखते हुए अगले 2-3 दिन में पांच लाख टन प्याज की खरीद शुरू करेगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, 'हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी चिंता का ध्यान रखा जाएगा। हम बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए अगले 2-3 दिन में पांच लाख टन प्याज की फसल की खरीद शुरू करेंगे।'

निर्यात पर रोक लगाने से व्यापारियों पर असर

उन्होंने कहा कि प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का असर व्यापारियों पर असर पड़ रहा है। इससे किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही। महाराष्ट्र में औसत मंडी (थोक) कीमत फिलहाल करीब 13-15 रुपये प्रति किलो हैं, जो पिछले साल के स्तर से करीब दोगुनी है। उन्होंने कहा, 'भले ही कीमतें गिरें, हम किसानों का ध्यान रखेंगे।' सचिव ने कहा कि सरकार मंडी दर पर बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीदारी करती है। हालांकि, यदि रेट उत्पादन लागत से नीचे आता है तो सरकार यह ध्यार रखती है कि कम से कम किसानों की लागत पूरी हो। साल 2023-24 में सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 17 रुपये किलो की औसत दर पर 6।4 लाख टन प्याज (रबी और खरीफ दोनों फसलें) खरीदी थीं।

अगले दो दिन में शुरू होगी प्याज की खरीद

उन्होंने कहा कि करीब पूरी मात्रा का निपटान कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में विशेष कार्याधिकारी निधि खरे ने कहा कि पिछले साल प्याज की खरीद जून में हुई थी। लेकिन इस साल यह अगले दो दिन में जल्दी शुरू होने जा रही है। दो नोडल सहकारी एजेंसियां नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) खरीद को अंजाम देंगी। खरीद के लिए, नेफेड और एनसीसीएफ (NCCF) को प्याज किसानों का पूर्व-पंजीकरण करना है ताकि यह तय किया जा सके कि किसानों को डीबीटी के जरिये उनके बैंक अकाउंट में किया जाए। खुदरा कीमत पर रबी प्याज उत्पादन में संभावित गिरावट के बारे में सचिव ने कहा कि देश में औसत खुदरा कीमत फिलहाल 33 रुपये प्रति किलो पर स्थिर हैं। सरकार ने आपूर्ति-मांग के अंतर को दो तरह से निपटने के लिए प्लान बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार विकिरण उपचार के जरिये 1,322 टन प्याज के स्व-जीवन (शेल्फ लाइफ) में सुधार का परीक्षण कर रही है और दूसरी बात यह है कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में किसानों को मौसम की स्थिति के आधार पर शुरुआती खरीफ फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लोकतंत्र को कमजोर करती है

अवसरवादी राजनीति...

देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है लेकिन चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि दलबदल का बढ़ता दौर कैसे रूके। राजनीति एवं राजनेताओं में नीति एवं सिद्धान्तों की बात प्रमुख होनी चाहिए लेकिन ऐसा न होना लोकतंत्र की बड़ी विसंगति है।

कांग्रेस में लगातार वफादार नेताओं का पलायन जारी है, नये नामों में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ, महाराष्ट्र के जिम्मेदार एवं पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, निशाना साधने वाले मुक्केबाज विजेंदर, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बाय-बाय कर दी है। इन सभी ने कांग्रेस के मुद्दाविहीन होने, मोदी के विकसित भारत के एजेंडे, राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति एवं कांग्रेस की सनातन-विरोधी होने को पार्टी से पलायन का कारण बताया है। कुछ भी कहे, यह राजनीति में अवसरवाद का उदाहरण है, इस तरह का बढ़ता दौर चिंताजनक है। भारत की राजनीति में दलबदल की विसंगति एवं विडम्बना आजादी के बाद से लगातार देखने को मिलती रही है। पिछले साढ़े सात दशक के भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पराभव के अक्स गाहे-बगाहे उजागर होते रहे हैं। दलबदल के बढ़ते दौर ने अनेक सवाल खड़े किये हैं। कल तक विपक्ष में जो नेता दागी होते थे, सतारूढ़ दल में शामिल होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनके दाग दाग नहीं रहते। राजनीति में निष्ठाएं बदलने की स्थितियां आम नागरिकों को उद्वेलित कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दागी नेता सत्ता की धारा में डुबकी लगाकर दूध का धुला घोषित हो जाता है।

हर बार चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में 'आयाराम-गयाराम' का खेल शुरु हो जाता है। विभिन्न दलों के प्रभावी नेताओं को अपने दल में शामिल कराने की होड़ मची है, कभी कोई एक दल बाजी मारती हैं तो कभी कोई दूसरा दल। सभी सेलिब्रिटी आखिर सत्ता की तरफ ही क्यों भागते हैं? पूर्व न्यायाधीश हो, पूर्व अधिकारी हो, अभिनेता हो या खिलाड़ी राजनीति में अपना भविष्य आजमाते रहे हैं। अगर भाजपा की विचारधारा किसी विजेंदर, गौरव या अनिल शर्मा जैसे लोगों हो क्यों अच्छी लगती है तो सवाल यह भी है कि पिछले पांच साल तक वे कांग्रेस में क्यों रहे? ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो गत वर्ष के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में एक पार्टी के चुनाव चिह्न पर उम्मीदवार थे तो अब दूसरी पार्टी का चुनाव चिह्न लेकर मैदान में उतरते दिख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इनदिनों भाजपा में जो विभिन्न दलों के तीस के लगभग राजनेता शामिल हुए हैं उनमें कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, टीएमसी, टीडीपी, एसपी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता शामिल हैं। क्या यह भाजपा के निश्चित जीत की संभावनाओं का परिणाम है या केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर का परिणाम है। निश्चिय ही यह स्थिति किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये शुभ नहीं कही जा सकती।

देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है लेकिन चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि दलबदल का बढ़ता दौर कैसे रूके। राजनीति एवं राजनेताओं में नीति एवं सिद्धान्तों की बात प्रमुख होनी चाहिए लेकिन ऐसा न होना लोकतंत्र की बड़ी विसंगति है। राजनीति में सबकुछ जायज है वाली सोच एवं स्वार्थ की नीति दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव का समय हर राजनेता के लिये अपने हित एवं स्वार्थ को चुनने का समय होता है, लेकिन उनके सामने लोकतंत्र के हिताहित का प्रश्न बहुत गौण हो जाता है। चुनावों में आचार संहिता के चलते कई प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में में दल-बदल पर नियंत्रण का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है, जबकि यह लोकतंत्र की जीवंतता एवं पवित्रता के लिये प्राथमिकता होनी चाहिए। सत्ता का स्वाद ही ऐसा होता है कि कोई भी राजनेता इससे अछूता नहीं रहता। इसीलिए आजकल दल बदलने का दौर खूब हो रहा है। यह बात दूसरी है कि ज्यादातर नेताओं में भाजपा का दामन थामने की होड़ मची है। एक दिन पहले भाजपा पर निशाना साधने एवं जीभर कर कोसने वाले नेताओं को एकाएक भाजपा इतनी अच्छी क्यों लगने लगती है? भाजपा को भी सोचना चाहिए कि आखिर ये अवसरवादी नेता जबभी उनके अनुकूल नहीं हुआ तो उसे भी बाय-बाय कर देंगे? भाजपा को यह भी देखना चाहिए कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर चंद घंटों पहले पार्टी में शामिल होने वाले को टिकट देना कहां तक उचित है। दलों को विचार करना ही होगा कि राजनीति के मायने चुनाव जीतना भर ही है या फिर वे विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देकर राजनीति को स्वस्थ रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज की ठेकेदारी राजनैतिक दलों एवं नेताओं ने ले रखी है, पर ईमानदारी से यह दायित्व कोई भी दल एवं नेता सही रूप में नहीं निभा रहा है। "सारे ही दल एवं नेता एक जैसे हैं" यह सुगबुगाहट जनता के बीच बिना कान लगाए भी स्पष्ट सुनाई देती है। राजनीतिज्ञ पारे की तरह हैं, अगर हम उस पर अँगुली रखने की कोशिश करेंगे तो उसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा। सभी दल राजनीति नहीं, स्वार्थ नीति चला रहे हैं।

भाजपा को अपने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना है, इसके लिये वह हर-तरह के समझौते कर रही है, दागी नेताओं को भी अपनी पार्टी में जगह दे रही है। ऐसे नेताओं के अपराधों पर भी परदा डाला जा रहा है। विडंबना है कि राजनीतिक निष्ठा बदलना इन नेताओं के लिये राहतकारी साबित हुआ है। वजह यह कि इन नेताओं से जुड़े अपराध के मामले ठंडे बस्ते में डाल दिये गए हैं। जबकि दलील यह दी जाती है कि मामले बंद नहीं हुए हैं, जरूरत पड़ी तो जांच और कार्रवाई भी होगी। जो विपक्ष के उन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुराग्रह एवं आग्रह के रूप में की जाती रही है। यही वजह है कि दल बदलने का फैसला राहत का रास्ता मान लिया जाता है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अचानक जांच एजेंसियां निष्क्रिय क्यों हो जाती हैं? क्यों किसी एजेंसी को लेकर अदालत को कहना पड़ता है कि फलां एजेंसी पिंजरे में बंद तोता है और मालिक की बोली बोलता है। विपक्ष के ऐसे तमाम आरोपों की तार्किकता हाल में आई एक रिपोर्ट दर्शाती है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद उनमें से 23 को राहत मिल गई है। इनमें से तीन मामले बंद हो गए हैं और बीस की जांच रुकी हुई है। ऐसे अवसरवादी नेता फिर किसी नई पार्टी में नहीं जाएंगे इसको क्या गारंटी है? अच्छे लोग राजनीति में यदि सिर्फ पद पाने के लिए ही आए तो उसे क्या माना जाए? ऐसी जानी-मानी हस्तियां भी हैं जो आज यहां और कल वहां के उदाहरण पेश कर चुकी हैं। ऐसी सलेब्रिटी को पार्टी में शामिल होते ही टिकट से पुरस्कृत कर दिया जाता है।

राजनीतिक दलों को इस बड़ी विसंगति एवं अवसरवादिता पर विचार तो करना ही चाहिए कि आखिर कौन, किस इरादे से पार्टी में आ रहा है। ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं कि नामी-गिरामी लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया, टिकट भी मिला और चुनाव जीते भी। उसके बाद जनता से जुड़ ही नहीं पाए और अगले चुनाव में इनका टिकट कट गया। स्वस्थ राजनीति में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, सक्षम हो, सुदृढ़ हो, स्पष्ट एवं सर्वजनहिताय का लक्ष्य लेकर चलने वाला हो। लेकिन स्वार्थी, अक्षम, दागी नेताओं को किसी भी दल में जगह देना यह उस दल की मजबूती एवं स्वस्थ राजनीति पर एक बदनुमा दाग है। विडम्बना है कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, मस्तिष्क नहीं। इसका खामियाजा हमारा लोकतंत्र भुगतता है, भुगतता रहा है। ज्यादा सिर आ रहे हैं, मस्तिष्क नहीं। जाति, धर्म, स्वार्थ और वर्ग के मुखौटे ज्यादा हैं, मनुष्यता के चेहरे कम। तभी राजनीति अवसरवादिता का अखाड़ा बनती जा रही है।

अमित शाह का दिग्विजय पर तंज, बोले-

आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले...

रायगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि उन्हें (दिग्विजय सिंह) राजनीति से स्थाई विदाई दी जाए। मेरी आप सभी से एक विनती है कि उनकी स्थाई विदाई करो, लेकिन- आशिक का जनाज़ा है ज़रा झूम के निकले...

अनुभवी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 33 साल के अंतराल के बाद राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे उनका क्षेत्र माना जाता है। दिग्विजय पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिग्गी राजा की सलाह से अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। मतदाताओं से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को 'स्थायी' चुनावी विदाई देने का आग्रह करते हुए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को फिदवी लाहौरी के एक प्रसिद्ध उर्दू दोहे का इस्तेमाल किया और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लोगों से उन्हें रिकॉर्ड अंतर से हराने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर को भारी जीत दिलाने का आह्वान किया। रायगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि उन्हें (दिग्विजय सिंह) राजनीति से स्थाई विदाई दी जाए। मेरी आप सभी से एक विनती है कि उनकी स्थाई विदाई करो, लेकिन- आशिक का जनाज़ा है ज़रा झूम के निकले... और इसके लिए आपको भारी मतों के अंतर से उनकी हार सुनिश्चित करनी होगी। राजगढ़ की जनता इन्हें घर बैठा दे।

अनुभवी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 33 साल के अंतराल के बाद राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे उनका क्षेत्र माना जाता है। दिग्विजय पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिग्गी राजा की सलाह से अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। इनकी सरकार तो आनी नहीं है, मगर मैं फिर भी आपसे पूछता हूं कि क्या शरिया कानून से देश चलना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात करके, पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाने की बात करती है।

भाजपा नेता ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द कहा था। ये पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कहकर बुलाते हैं, जाकिर नाइक को गले लगाते हैं, अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हैं और PFI पर बैन का भी विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बार आए और बहुत बार गए। अब समय आ गया है, इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों को करनी है।

शाह ने कहा कि कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमिपूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्रीराम कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया, लेकिन वो नहीं गए। क्योंकि ये अपनी वोटबैंक से डरते हैं। जो निमंत्रण मिलने के बाद न मंदिर गए, न अयोध्या गए, इन लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता।

देश जैसे-जैसे विकसित होगा, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या कम होगी

आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सदस्य आशिमा गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या भविष्य में कम गंभीर होगी, क्योंकि विविध स्रोतों के साथ आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विशिष्ट खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से निपटने में मदद कर सकती हैं। भारत में घरेलू बजट में भोजन की हिस्सेदारी अधिक होने की बात पर जोर देते हुए गोयल ने कहा कि नीति के कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होने की जरूरत है, क्योंकि स्थिर कृषि कीमतें मुद्रास्फीति से परे वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, जैसे-जैसे भारत विकसित होगा, इस समस्या (उच्च खाद्य मुद्रास्फीति) की गंभीरता कई कारणों से कम होती जाएगी। विविध स्रोतों वाली आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विशिष्ट वस्तुओं के दाम बढ़ने पर उनसे निपटने में मदद करेंगी। गोयल ने कहा कि किसी ने भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में टमाटर या प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में नहीं सुना है। उन्होंने कहा, हमारे पास स्वाभाविक रूप से विविध भौगोलिक क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बेहतर एकीकृत बाजार जलवायु परिवर्तन से प्रेरित खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने में मदद कर सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर पांच महीने के निचले स्तर 4।85 प्रतिशत पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होना रहा। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति मार्च में 8.52 प्रतिशत रही, जो फरवरी में 8.66 प्रतिशत थी। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि मुद्रास्फीति 2024-25 में घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी। यह 2023-24 में 5.4 प्रतिशत और 2022-23 में 6.7 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

कांग्रेसी की सरकारों ने गांवों के साथ सौतेला व्यवहार किया...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकारों पर आजादी के बाद देश में गांवों के साथ सौतेला व्यवहार करने और उनका भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन, शिलान्यास करने के बाद रीवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने स्थिति को बदल दिया है और पंचायतों को भरपूर अनुदान दिया है।

मोदी ने कहा, आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई उसने ही गांव के लोगों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोगों, सड़कों, भंडार के स्थानों, स्कूलों ,बिजली, अर्थव्यवस्था सभी को कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी प्राथमिकता में सबसे नीचे की पायदान पर रखा गया। देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार कर देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मोदी ने कहा, पहले की सरकारें गांवों के लिए पैसा खर्च करने में हिचकिचाती थीं क्योंकि वे वोट बैंक नहीं थे, इसलिए उनकी उपेक्षा की गई। कई राजनीतिक दल गांव के लोगों को बांट कर अपनी दुकान चला रहे थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने गांवों के साथ हुए इस अन्याय को खत्म किया है और उनके विकास के लिए तिजोरी खोल दी है।प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रीवा में आयोजित कार्यक्रम से देश भर के 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि वर्चुअली जुड़े हैं। उन्होंने कहा, यह निश्वत रुप से भारत के लोकतंत्र के एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के 10 वर्षों में, तत्कालीन केंद्र सरकारों की मदद से लगभग 6,000 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा, लेकिन हमारी सरकार ने आठ साल की भीतर 30 हजार से अधिक नए पंचायत भवनों का निर्माण कराया है।

2014 के बाद से हमने पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया

प्रधानमंत्री ने कहा, 2014 के बाद से हमने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया गया। आज उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। आज भारत की ग्राम पंचायतें गांव के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों पर पंचायत व्यवस्था को नजर अंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा, जो व्यवस्था सैकड़ों साल पहले थी उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांवों में बसती है लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती के राज के नाम पर खानापूर्ति जरुर की गयी लेकिन पंचायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी जरूरत थी।

'डिजिटल क्रांति के दौर में पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है'

मोदी ने मौजूदा शासन में ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटल विकास का जिक्र करते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-ग्राम स्वराज-जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) एकीकृत पोर्टल सोमवार को जारी किया गया है जिससे पंचायतों के माध्यम से होने वाली उपार्जन की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा, गांवों में घरों की संपत्ति के कागजात को लेकर बहुत परेशानियां है। इस वजह से कई तरह के विवाद और अवैध कब्जे की बातें होती हैं। लेकिन अब, ये सभी चीजें 'पीएम स्वामित्व योजना' के साथ बदल रही हैं।'

'गांवों में अब बैंक संचालित हो रहे हैं: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गांवों में अब बैंक संचालित हो रहे हैं इससे ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी और कारोबार में मदद हो रही है। मोदी ने कहा, हमने जन धन योजना में गांवों में 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले हैं। हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए गांवों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 70 से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर (सिस्टम) से जोड़ा था।

उन्होंने कहा, लेकिन हमारी सरकार है, जिसने देश की दो लाख से अधिक पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्था, हर जनप्रतिनिधि, हर नागरिक को जूझना होगा और यह तभी संभव है जब हर सरकारी सुविधा बिना किसी भेदभाव के 100 प्रतिशत लाभार्थियों तक तेजी से पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा, इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के समर्थन के चलते उनका रेडियो प्रसारण मन की बात का 100 वां संस्करण पूरा करने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि वह भी 100वें एपिसोड (30 अप्रैल को) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस अवसर पर उनके साथ जुड़ने का आग्रह किया।

पाकिस्तानी नेता भी कहते हैं कि काश मोदी उनके देश के नेता होते : सीएम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के नेता भी कहते हैं कि काश उनके देश में भी मोदी जैसा कोई नेता होता। उन्होंने साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके द्वारा ''बोए गए बीजों के कारण भारत का विभाजन'' हुआ। यादव ने शुक्रवार शाम को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान सभाओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि पड़ोसी देश में अस्तित्व का संकट है।

उन्होंने कहा, (पूर्व प्रधानमंत्री) नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान के नेता लगातार कह रहे हैं कि काश नरेन्द्र मोदी वहां (पाकिस्तान में) होते। अगर आप नेता हैं तो ऐसेनेता बनें कि आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। यह नेता (मोदी) हमें गौरवान्वित कर रहा है।'' उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी के माथे पर देश को भारत और पाकिस्तान में बांटने का कलंक है। यादव ने कहा, देश के विभाजन के समय कोई भाजपा या जनसंघ नहीं था। कांग्रेस द्वारा बोए गए बीज के कारण देश का विभाजन हुआ। आधा पंजाब वहां (पाकिस्तान में) चला गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के समय लोगों में डर पैदा किया। यादव ने कहा, जब अनुच्छेद 370 को हटाया जा रहा था, तब कांग्रेस ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो देश में खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां तभी बहेंगी, जब रगों में खून होगा। आपकी (कांग्रेस) रगों में पानी है। अनुच्छेद 370 का कलंक मिटाने पर देश जश्न मना रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग इतने खुश हैं कि पीओके के लोग भी भारत में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में गुजारा करना मुश्किल है। होशंगाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा।

हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर होगा कड़ा मुकाबला, कंगना रनौत बनाम विक्रमादित्य

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वह आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।

लोकसभा चुनाव 2024: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वह आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। विक्रमादित्य की मां और हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने घोषणा की कि विक्रमादित्य सिंह मंडी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक रहे विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और राज्य कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, जो मंडी सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। वह प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। हिमाचल के मंत्री ने रनौत को राज्य के लिए उनके दृष्टिकोण पर उनके साथ बहस करने की चुनौती दी। उन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वह रनौत को कुछ 'अच्छी सद्बुद्धि' देने के लिए भगवान राम से प्रार्थना करेंगे। सिंह ने कहा 'आपने क्या योगदान दिया है और निकट भविष्य में आपकी भूमिका क्या होगी।

मंडी से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में भविष्य के लिए आपकी दृष्टि और योजना क्या है? आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह करने और उनका समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं।'

दुनिया और अधिक युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती - यूएन चीफ

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संकट पैदा होने की आशंका के बीच रविवार को जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्किये और मिस्र के समकक्षों से बातचीत की जबकि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सऊदी अरब एवं इजराइल के रक्षा मंत्रियों से बात की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को इज़राइल पर ईरान के सप्ताहांत हमले पर एक बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संघर्ष में गहरे उतरने के खिलाफ चेतावनी दी। गुटेरेस ने कहा कि न तो क्षेत्र और न ही दुनिया अधिक युद्ध बर्दाश्त कर सकती है। उन्होंने सुरक्षा परिषद को बतायामध्य पूर्व कगार पर है। क्षेत्र के लोग विनाशकारी पूर्ण पैमाने के संघर्ष के वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं। अब तनाव को कम करने और कम करने का समय है।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संकट पैदा

होने की आशंका के बीच रविवार को जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्किये और मिस्र के समकक्षों से बातचीत की जबकि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सऊदी अरब एवं इजराइल के रक्षा मंत्रियों से बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के जी-7 देशों के नेताओं से हुई बातचीत के बाद इस संकट से निपटने में कूटनीतिक तेजी आयी है। बाइडन ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर अलग से बातचीत की। ईरान ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए रविवार तड़के इजराइल पर हमला कर दिया और उस पर सैंकड़ों ड्रोन, बैलेस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइल दागीं। ईरान के इस हमले ने पश्चिम एशिया को क्षेत्रव्यापी युद्ध के करीब धकेल दिया है। इजराइली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगारी ने कहा कि ईरान ने कई ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलेस्टिक मिसाइल दागीं, जिनमें से अधिकतर को इजराइल की सीमाओं के बाहर नष्ट कर दिया गया।

अब देश में विदेशियों के अंग प्रत्यारोपण की होगी जांच, 48 घंटे में आईडी देना जरूरी

भारत आकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले सभी विदेशी मरीजों की जांच होगी। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने राज्यों को दिए आदेश में कहा है कि थोटा अधिनियम 1994 के तहत जिम्मेदार एजेंसियों के जरिये उन सभी अस्पतालों में विदेशियों के प्रत्यारोपण की जांच कराई जाए, जिन्होंने भारत आकर अंगदान या फिर प्रत्यारोपण कराया है। आदेश के मुताबिक, अंग प्रत्यारोपण के 48 घंटे के भीतर दाता और अंग लेने वाले दोनों की आईडी केंद्रीय एजेंसी के साथ साझा करनी होगी। अभी तक यह प्रक्रिया मृत दाता से प्राप्त अंगों के मामले में चल रही है, लेकिन अब इसे जीवित अंगदाता के मामले में भी अनिवार्य किया है।

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल ने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि प्रत्येक राज्य को अपने अस्पतालों में होने वाले अंग प्रत्यारोपण की जानकारी हर माह दिल्ली भेजनी होगी, ताकि सरकार प्रत्येक प्रत्यारोपण की समीक्षा कर सके। उन्होंने प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों की नियमित निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करने का आदेश भी दिया है, जिसके जानकारी महानिदेशालय को भी देना जरूरी होगा।

डॉ. अतुल गोयल का कहना है कि सभी राज्यों को अंग प्रत्यारोपण के मामले में जांच शुरू करनी चाहिए। अगले 15 दिन के भीतर इसकी पूरी रिपोर्ट महानिदेशालय को भेजने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि राज्यों ने अंग प्रत्यारोपण में लापरवाही या किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

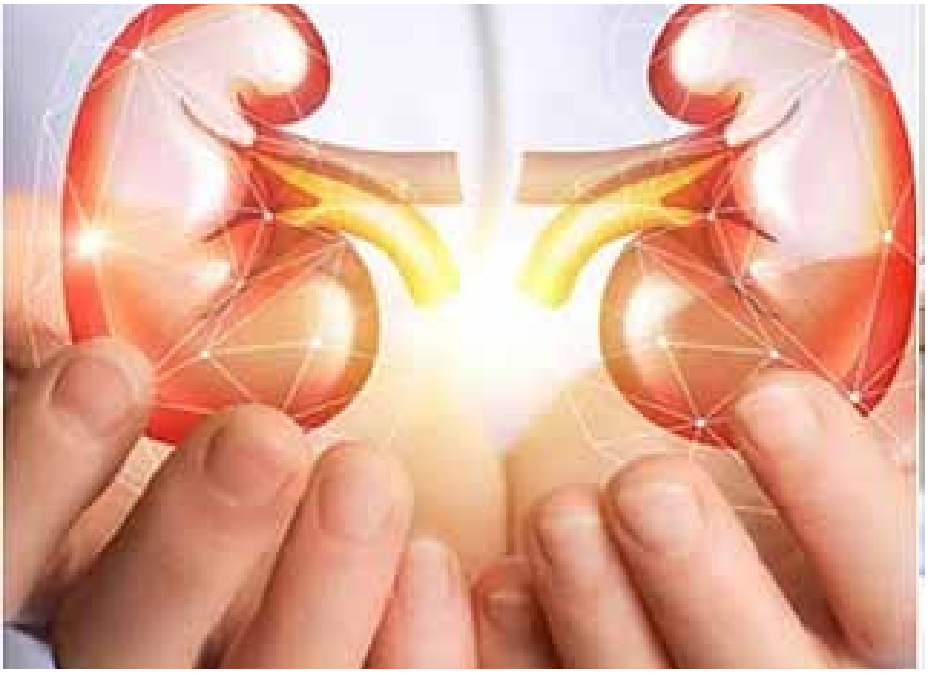

दरअसल, हरियाणा और राजस्थान में अंग प्रत्यारोपण को लेकर एक गिरोह सामने आया है, जिसके तार इन दो राज्यों के अलावा झारखंड और बांग्लादेश से जुड़े हैं। वहीं, कुछ महीने पहले म्यांमार और दिल्ली के एक अस्पताल के बीच भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। इसके अलावा साल 2016 में किडनी रैकेट में भी नेपाल और भूटान से भारत आकर अपने अंग दान करने की घटना हुई।

नकुलनाथ पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा वार

'लोकतंत्र को नोट तंत्र के माध्यम से खरीदना चाहती है कांग्रेस'

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के बेटे और छिंदवाड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि नकुल नाथ 'नोट-तंत्र' के जरिए 'लोकतंत्र' खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए टिप्पणी की और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से नाथ के घर का निरीक्षण करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों से कुछ जगहों पर शराब बांटी जा रही है और हमने इसकी शिकायत की है। कांग्रेस नेता गिरीश साहू के पास से 4.94 लाख रुपये नकद बरामद किये गये और जिन नामों पर उन्होंने पैसे लिये थे, उनकी सूची भी बरामद की गयी। उनके साथ तीन और कांग्रेस कार्यकर्ता थे जो भाग गये। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे लगता है कि वे (कांग्रेस) 'नोट-तंत्र' के जरिए 'लोकतंत्र' खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।' नकुलनाथ बीजेपी से बिल्कुल डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें (नाथ को) अपनी हार साफ दिख रही है, इसीलिए उन्होंने नोट-तंत्र का सहारा लिया, कुछ जगहों पर बर्तन और शराब बांटे। उन्होंने

कहा कि अहीर समुदाय के कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि उन्हें 15 लाख रुपये के मंगल भवन की पेशकश की गई थी, जिसे कांग्रेस नेता ने कहा था कि यह उनके लिए बनाया जाएगा। इस तरह नकुलनाथ 'नोट-तंत्र' के जरिए 'लोकतंत्र' खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हम ईसीआई से उनके घर का निरीक्षण करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि उनके आवास पर नोटों के बंडल हैं जिनका उपयोग वह मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए कर रहे हैं।

मंत्री ने यह भी कहा कि वह चुनाव आयोग से छिंदवाड़ा लोकसभा को संवेदनशील संसदीय सीट घोषित करने और उनके (नाथ) वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और नकुलनाथ इस चुनाव में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि पूरी छिंदवाड़ा लोकसभा को संवेदनशील संसदीय सीट घोषित किया जाए और उनके वाहनों की नियमित जांच की जाए। क्योंकि खूब शराब, बर्तन और नकदी बांटी जा रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है और मेरा मानना है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। राज्य की पांच अन्य संसदीय सीटों के साथ छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू का मुकाबला कांग्रेस के नकुल नाथ से है।

शाह बोले- मोदी के पास दस साल का रिकॉर्ड और 25 साल की प्लानिंग है

'बार-बार फेल हो रही राहुल की लॉन्चिंग'

शाह ने कहा कि बीते 10 वर्ष में मोदी जी ने असंभव दिख रहे कार्यों को पूरा किया है। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और आने वाले 25 वर्षों की प्लानिंग है। इसलिए इस बार के चुनाव में मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर की जनसभा में कहा कि दस साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असंभव दिखने वाले कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास दस साल का रिकॉर्ड है और 25 साल की प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। उन्होंने कहा कि मैं इस वीरभूमि की माताओं से, वीरांगनाओं से मैं कहने आया हूं कि कांग्रेस ने 'वन रैंक वन पेंशन' का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। आपने 2014 में जब मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तब उन्होंने 'वन रैंक वन पेंशन' का वादा पूरा कर देश के जवानों और उनके परिवारों का सम्मान किया। शाह ने कहा कि बीते 10 वर्ष में मोदी जी ने असंभव दिख रहे कार्यों को पूरा किया है। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और आने वाले 25 वर्षों की प्लानिंग है। इसलिए इस बार के चुनाव में

मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी यहां आकर कहते हैं कि कश्मीर से राजस्थान के लोगों को क्या लेना-देना है। क्या कश्मीर, राजस्थान का नहीं है? कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों से वोट बैंक की लालच में धारा-370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त, 2019 को धारा-370 को समाप्त कर कश्मीर में तिरंगा फहराया।

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नदियों को जोड़ने का विरोध करती है। आप घबराना मत! मैं आपसे वादा करता हूं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यहां आएगा और पूरे अलवर में पानी पहुंचेगा।

दो वर्ष के पहले नहीं बदल सकेंगे कोर्स, यूनिफार्म की पब्लिक डोमेन में देनी होगी जानकारी...

प्रदेश में अब निजी स्कूलों की मनमानी पर कसेगी नकेल...

नया शिक्षण सत्र शुरू होने के साथ ही निजी स्कूल संचालकों की मनमानी भी शुरू हो गई है। इससे पालकों को निर्धारित विक्रताओं से ड्रेस, किताब, कापी सहित अन्य शिक्षण सामग्री खरीदनी पड़ रही है। इसे देखते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने स्कूल संचालक, पाठ्य पुस्तक प्रकाशक और विक्रेताओं पर नकेल कसने की तैयारी कर ली हैं। इसको लेकर कलेक्टर ने गुरुवार को निजी स्कूल संचालक सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसके बाद कोर्स और अन्य शिक्षण सामग्री को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी निजी स्कूलों को कोर्स टाई, बेल्ट, ड्रेस की जानकारी पब्लिक डोमेन में भी अपलोड करने होंगे।

बदलाव से पहले लेनी होगी इजाजत : कलेक्टर ने बताया कि नई गाइडलाइन का सभी निजी स्कूल, एमपी बोर्ड, सीबीएससी सहित अन्य संवर्ग के स्कूलों को पालन करना होगा। बैठक में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल हर वर्ष जनवरी में ही एनसीईआरटी से जुड़ी पुस्तकों की सूची जारी कर देता है। नई गाइडलाइन के तहत अब निजी स्कूल संचालकों को भी इसका पालन करना पड़ेगा। कलेक्टर ने बताया कि कोई भी स्कूल संचालक दो वर्ष के पहले संस्थान में पढ़ाए जा रहे कोर्स में बदलाव नहीं कर सकेगा। बदलाव करने की स्थिति में अनुमति लेना जरूरी होगा। इस नई गाइडलाइन से राजधानी के लाखों पालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उनको महंगे दामों में कोर्स सहित अन्य सामग्री नहीं खरीदनी होगी।

निजी स्कूलों की होगी जांच : राजधानी के सभी निजी स्कूलों की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी ने चार समितियां गठित की हैं। ये समितियां प्रत्येक स्कूल में जाकर वहां के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही पुस्तक और अन्य शिक्षण सामग्री की जानकारी जुटाएंगी, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर को पेश की जाएगी। प्रत्येक स्कूल की जांच होने से शिक्षा विभाग के पास रिकार्ड एकत्रित हो जाएगा कि किस स्कूल में कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। पुस्तकों की जानकारी पब्लिक डोमेन में आने से ज्यादा से ज्यादा दुकानदार इन किताबों को बेच सकेंगे।

महंगी पुस्तकों से पढ़ाने पर की जाएगी जांच

बैठक में बताया गया कि कई निजी स्कूलों में महंगी किताबों से पढ़ाई कराई जा रही है। इन पुस्तक की कीमत अधिक होने की वजह से पालकों को खरीदने में दिक्कत होती है। इस वजह से इनकी कीमतों को लेकर भी जांच की जाएगी।

▸ पुस्तक विक्रेताओं और स्कूल संचालकों के खिलाफ पालक लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायतों के आधार पर जांच कर धारा 144 के तहत एफआइआर और दो लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसका पालन अब सभी स्कूल संचालकों को करना होगा।

- कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, भोपाल

भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी

बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, गरीबों को मिलेगा फ्री राशन...

भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी संकल्प पत्रा जारी किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाजपा मुख्यालय में पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के संकल्प पत्र प्रस्तुत किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान को सशक्त करेगा। भाजपा में संकल्प पत्र में मोदी की इन गारंटी का विशेष जिक्र है, जिनका उल्लेख पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया।

संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी

- देश में जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, लोगों को सस्ती दवाएं लगातार मिलती रहेगी।
- 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
- देश में मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी।
- आने वाले 5 वर्ष नारीशक्ति की नई भागीदारी के होंगे।
- भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब हम 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे।
- देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा।
- सस्ते सिलेंडर के बाद अब पाइप से सस्ती रसोई गैस घर-घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे।
- नमो ऐप से मिले 4 लाख सुझाव
- राजनाथ सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र तैयार करने के लिए 4 लाख सुझाव NAMO ऐप के माध्यम से भी आए और करीब 10 लाख सुझाव
- वीडियो के माध्यम से आए। सभी बातों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है। हर विषय का 360 डिग्री विश्लेषण करने के बाद हमने विषयों को 24 समूह में बांटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन संकल्पों को हम यहां रखा हैं वो 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को विस्तृत भी करेंगे, आकार भी देंगे और इसे साकार करने में भी ये मददगार साबित होंगे।'

10 साल के काम का उल्लेख

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने कहा कि बीते 10 साल इस बात का प्रमाण है कि मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है और बारहमासी सड़कें बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव सशक्त होंगे और ऑप्टिकल फाइबर लाइन गांव तक पहुंच जाएगी, लेकिन आज खुशी है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1.2 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा दिया गया है और उन्हें इंटरनेट सुविधाओं से भी जोड़ा गया है। देश की 25 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी अब 1 प्रतिशत से भी कम हो गई है।

देशवासियों से किया हर वादा पूरा किया

इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया हुआ हर वादा पूरा किया है। चाहें 2014 का संकल्प पत्र हो या 2019 का घोषणापत्र हो पीएम मोदी के नेतृत्व में हर संकल्प को पूरा किया है। जब पीएम मोदी के नेतृत्व में हम 2014 का चुनाव लड़ा था तो उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तब मोदी जी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें उसे हम पूरा करें। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 2019 में जो भी संकल्प हमने लिए आज 2024 तक उन सबको पूरा करने में हमने कामयाबी हासिल की है।

सियासी सरगर्मियों के बीच 'नागरिकता' चुनावी मुद्दा बनता नहीं दिख रहा...

सीएए पर सन्नाटा क्यों है?

जिस कानून के चलते तकरीबन पूरा उत्तर भारत महीनों तक धरना और प्रदर्शनों का गवाह बना रहा, जिसके विरोध की आड़ में देश की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए, क्या वह अब चुनावी मुद्दा नहीं रहा? यह सवाल नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के संदर्भ में उठ रहा है। लेकिन मौजूदा चुनावी दौर में इस कानून की खुले तौर पर कहीं चर्चा सुनाई नहीं दे रही है।

संसद की मंजूरी के बाद जिस अल्पसंख्यक वर्ग ने इस कानून का विरोध किया था, हो सकता है कि उस समुदाय के बीच अब भी इसे लेकर कुछ सवाल हों, लेकिन हर तरफ चुप्पी है। अगर कहीं इसकी थोड़ी-बहुत चर्चा है भी, तो वह पश्चिम बंगाल और केरल जैसे ही राज्य हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वामपंथी दलों का असर है। दिलचस्प यह है कि आचार संहिता लागू होने के दो दिन पहले यानी 14 मार्च को ही अमित शाह कह चुके हैं कि किसी भी हालत में सीएए वापस नहीं लिया जाएगा।

चुनाव के मुद्दे मोटे तौर पर दो तरह से बनते हैं। एक तो किसी मुद्दे, विषय या कानून को लेकर जनता के बीच गहरा असंतोष हो, जिसकी बुनियाद पर वोटों की फसल काटने के लिए विपक्षी दल उसे हवा दे रहे हों या फिर किसी नीति के जरिये सरकार कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी हो या सरकार के किसी फैसले के चलते सकारात्मक बदलाव आया हो। नाकामियों और असंतोष को जहां विपक्षी खेमा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, वहीं सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों और कामयाबियों को चुनावी मैदान में लोकमत संग्रह का जरिया बनाता है। सत्ताधारी भाजपा प्रत्याशी स्थानीय स्तर पर भले ही सीएए को उपलब्धि बता रहे हों, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भाजपा अभी तक इसे चुनावी मुद्दा बनाते नहीं दिख रही है। वैसे भी भाजपा ने अभी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस 'न्याय पत्र' नाम से अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। लेकिन उसके घोषणा पत्र में इस पर चुप्पी साध ली गई है।

दिसंबर, 2019 में जब संसद के दोनों सदनों ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी, तब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और एआईएमआईएम ने कड़ा विरोध जताया था। वामपंथी दल और राष्ट्रीय जनता दल भी इसके विरोध में थे। मुस्लिम संगठन भी इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे।

पीएफआई जैसे संगठन इस कानून के विरोध में देश विरोधी षड्यंत्र रचने में पीछे नहीं रहे। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका तो इस कानून के विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बन गया। देश भर में, विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में जबर्दस्त विरोध-प्रदर्शन हुए। उस समय लगता था कि यह विरोध-प्रदर्शन और धरना अंतहीन रहेगा। लेकिन इस बीच कोरोना महामारी आ गई और शाहीन बाग का धरना खत्म हुआ। लेकिन पूर्वी दिल्ली का इलाका दंगे की आग में धधक उठा था। इस कानून के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय स्तर पर एक खास वर्ग ने निशाना बनाया। इस कानून के लिए अमित शाह विशेष रूप से निशाने पर रहे, क्योंकि इस कानून को पारित कराने में उनकी ही भूमिका प्रमुख रही। भाजपा की पार्टी लाइन पर इस कानून में संशोधन करने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। विरोध प्रदर्शनों के जरिये विपक्षी खेमे और कानून विरोधियों ने सरकार को झुकाने की खूब कोशिश की, लेकिन सरकार ने कानून वापस नहीं लिया। दरअसर अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में यह भ्रम फैला कि अगर यह कानून पारित हुआ, तो उनकी नागरिकता चली जाएगी, जबकि सरकार इससे बार-बार इन्कार करती रही। इन्हीं वजहों से माना जा रहा था कि चुनाव के दौरान यह कानून कम से कम विपक्षी खेमे के जरिये मुद्दा जरूर बनेगा। लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से इस मसले को कम से कम चुनावों तक के लिए टाल दिया है। हालांकि माकपा अपनी ओर से लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर कर रही है। उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इस कानून को हटाने का वादा किया है। इसके अलावा, कांग्रेस की चुप्पी पर माकपा भी सवाल उठा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तो इसको लेकर कांग्रेस को खरी-खोटी सुनाई है।

सीजन से पहले आम के शौकीनों के लिए खुशखबरी, इस बार होगा बंपर उत्पादन!

गर्मियां शुरू होने के साथ ही आने वाले महीनों में आम की फसल भी दस्तक देने के लिए तैयार है। कुल इलाकों में आम का सीजन मई- जून में शुरू होने की उम्मीद है। आईसीएआर (ICAR) सेंट्रल इंस्टीट्यूट फार सबट्रापिकल हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर टी दामोदरन ने कहा कि इस साल आम का उत्पादन 14 प्रतिशत बढ़कर 24 मिलियन टन होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल-मई महीने में लू की आशंका के बावजूद आम की पैदावार पर इसका कोई खास असर नहीं दिखाई देगा। बस किसानों को मई के महीने में पानी का ध्यान रखना होगा ताकि ज्यादा फल न झड़ें।

सामान्य से ज्यादा गर्मी होने की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की तरफ से जारी किये गए ग्रीष्मकालीन पूर्वानुमान में बताया गया कि गर्मी की लहर का कहर इस बार और भीषण हो सकता है। यह सामान्य दो से चार दिन की बजाय 10-20 दिन तक रह सकता है। दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश भागों, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके में सामान्य से ज्यादा गर्मी होने की संभावना है। दामोदरन ने बताया, 'आम में फूल (मंजर) आना फल लगने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। अनुकूल मौसम के कारण, आम में फूल आना लगभग खत्म हो गया है। परागण सामान्य है और फल लगने शुरू हो गए हैं। सामान्य गर्मी पैदावार को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फसल को मदद करेगी।'

..इस बार आम की फसल अच्छी रहने की संभावना

उन्होंने कहा कि आम की फसल की संभावनाएं अभी अच्छी हैं। फसल साल 2023-24 (जुलाई-जून) में कुल उत्पादन बढ़कर 2।4 करोड़ टन हो सकता है, जबकि फसल वर्ष 2022-23 में यह 2।1 करोड़ टन था। दक्षिण भारत में आम का उत्पादन बंपर देखा जा रहा है, जो देश के कुल उत्पादन में 50 प्रतिशत का योगदान देता है। पिछले साल मौसम की गड़बड़ी के कारण दक्षिणी राज्यों को 15 प्रतिशत नुकसान का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस साल स्थिति बेहतर है। आम भारत का एक महत्वपूर्ण फल है और इसे 'फलों का राजा' कहा जाता है। भारत प्रमुख आम उत्पादक देश है, जो विश्व के उत्पादन में करीब 42 प्रतिशत का योगदान देता है।

सिंचाई करके मिट्टी की नमी बनाए रखें

दामोदरन के अनुसार, जलवायु फूल आने और फल लगने में भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हालांकि, सामान्य से अधिक गर्मी की स्थिति में, किसानों को सावधानी बरतने और हल्की सिंचाई करके मिट्टी की नमी को बनाए रखने की जरूरत है। इससे फल का गिरना कम हो जाता है। उन्होंने किसानों को उत्तरी मैदानी इलाकों के आम उत्पादक क्षेत्रों में आक्रामक कीटों के हमले, विशेषकर थ्रिप्स कीट से सावधान रहने की सलाह दी। दामोदरन ने कहा कि आम के कई बागों में थ्रिप्स की आबादी कई गुना बढ़ गई है। भोजन की तलाश में, थ्रिप्स कीट पुष्प भागों से नवगठित फलों की ओर पलायन करेंगे। उन्होंने कहा कि फसल को बचाने के लिए किसान तुरंत कीटनाशक, विशेष रूप से इमिडाक्लोप्रिड, लगभग चार मिलीलीटर (एमएल) प्रति लीटर पानी या थियामेथैक्सम 0।4 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव कर सकते हैं।

तकनीक से खेती करना फायदेमंद, पराली जलाने में आएगी कमी...

डेवलपमेंट एजेंसी आईडीएच के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (ग्लोबल) डैन वेन्सिंग ने कहा कि रीजनरेटिव फार्मिंग (Regenerative Farming), मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कवर फसलें (Cover Crops) उगाने और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में पहुंचाने से न केवल किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, बल्कि पराली जलाने (Stubble Buring) के मामलों में भी कमी आएगी। कृषि में 'कवर' फसलें वे पौधे हैं जो कटाई के उद्देश्य से नहीं बल्कि मिट्टी को ढकने के लिए लगाए जाते हैं ताकि हवा से भूमि का क्षरण (Soil Erosion) न हो। हालांकि, उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के दीर्घकालिक समाधान के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी जरूरी होगी। वेन्सिंग ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप रीजनरेटिव फार्मिंग कैसे कर सकते हैं? कृषि क्षेत्र का विस्तार किए बिना आप पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं? उन्होंने कहा, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी, नए समाधान की जरूरत है। हम इन नए समाधानों पर काम करने और अलग-अलग परिदृश्यों में उनका परीक्षण करने के लिए सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं।

नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने की वकालत : वेन्सिंग ने कहा, हमें अलग-अलग प्रक्रियाओं के जरिए पराली को बाहर निकालने, पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में पहुंचाने के तरीके खोजने की जरूरत है। उन्होंने उर्वरता बनाए रखने के लिए मिट्टी में कार्बनिक कार्बन सामग्री को बढ़ाने के लिए नई

टेक्नोलॉजीज को अपनाने की वकालत की। वेन्सिंग ने कहा कि पराली जलाने (जो उत्सर्जन का कारण बनता है) के बजाय ... मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए नए तरीकों को लागू करने से पैदावार बढ़ाने और CO_2 उत्सर्जन को कम करने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति होगी।

किसानों को नहीं मिल रहा फसल का उचित दाम : सीईओ ने कहा कि दुनिया भर में किसानों के विरोध प्रदर्शनों की संख्या में बढ़ोतरी मुख्यतः इसलिए है क्योंकि उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, यहां तक कि मेरे गृह देश (नीदरलैंड) में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसकी मुख्य वजह देश से परे यह है कि किसान वैल्यू चेन के अंतिम छोर पर है। वेन्सिंग ने कहा, एक समाज के तौर पर हम जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के कारण पर्यावरण स्थिरता चाहते हैं। इसकी जिम्मेदारी अक्सर पूरी तरह से किसानों पर आ जाती है। अगर हम बदलाव के इस दौर में उनका समर्थन नहीं करते हैं और यदि हम सारा जोखिम तथा लागत किसान पर डालते हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा।

अच्छी खबर... बंपर स्टॉक के लिए सरकार खरीदेगी 5 लाख टन प्याज

किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने NCCF और नैफेड को बफर स्टॉक के लिए सीधे किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है। बता दें कि रबी-2024 की फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है। खरीद के लिए, NAFED और NCCF को प्याज किसानों का पहले पंजीकरण करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए। रबी प्याज देश की प्याज उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश में वार्षिक उत्पादन का 72 -75% योगदान देता है। साल भर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी मौसम का प्याज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें खरीफ प्याज की तुलना में बेहतर भंडारण समय है और इसे नवंबर-दिसंबर तक आपूर्ति के लिए संग्रहीत किया जा सकता है।

आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने NAFED और NCCF के माध्यम से बफर स्टॉक के लिए 2023-24 के दौरान लगभग 6।4 LMT प्याज

खरीदा था। NAFED और NCCF द्वारा लगातार खरीद ने 2023 में पूरे वर्ष प्याज किसानों के लिए लाभकारी कीमतों की गारंटी दी है। इसके बाद, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पिछले वर्ष के दौरान एनसीसीएफ, एनएएफईडी, केंद्रीय भंडार (Kendriya Bhandar) और अन्य राज्य नियंत्रित सहकारी समितियों द्वारा संचालित खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज बेचा है। समय पर हस्तक्षेप और कैलिब्रेटेड रिलीज ने किसानों की आय को प्रभावित किए बिना खुदरा कीमतों को प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया है।

वैश्विक आपूर्ति परिदृश्य और अल नीनो के कारण सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्याज निर्यात को रेगुलेट करने के लिए नीतिगत उपाय करने की जरूरत पड़ी। इन उपायों में 19 अगस्त 2023 को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाना, 29 अक्टूबर 2023 से 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) लगाना और 2020 से निर्यात पर प्रतिबंध शामिल है। **इन देशों को प्याज निर्यात की मंजूरी** : मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतों और वैश्विक उपलब्धता संबंधी चिंताओं के बीच घरेलू उपलब्धता के कारण प्याज निर्यात प्रतिबंध को बढ़ाने का हालिया फैसला जरूरी हो गया है।

मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और समाचार पत्र कर्म साक्षी का सयुंक्त आयोजन

फाग महोत्सव में राधा कृष्ण ने खेली फूलों की होली...

मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ इन्दौर जिला इकाई और कर्मसाक्षी समाचार पत्र द्वारा स्वामी प्रीतमदास सभागृह में फाग उत्सव और होली मिलन समारोह का रंगारंग आयोजन किया गया। इस मौके पर राधा और कृष्ण ने फूलों के संग सुंदर होली खेली। आयोजक व संस्था की उपाध्यक्ष सरिता शर्मा ने बताया कि उत्सव की शुरूआत् रास से हुई।होली के गीतों और भजनों पर प्रस्तुति हुई। सिने अभिनेत्री सारिका दीक्षित ने होली के गीतों पर मनोहारी नृत्य कर सबको भाव विभोर कर दिया। होरी खेले रघुवीरा अवध मे होरी खेले रघुवीरा ..अरे जारे नटखट... रंग बरसे भीगे चुनर वाली गीतों पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुति हुई। विजय पाठक और सोनिया पाठक ने सुरों की महफ़िल से माहौल को संगीतमय कर दिया। राधा कृष्ण की जोड़ी ने सुंदर रास कर सबको मथुरा वृन्दावन की याद दिला दी।

मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने बताया कि उत्सव मे राधा कृष्ण ने इतने फूल बरसाए कि फूलों की पीली गुलाबी चादर बिछ गई। अतिथि स्वागत जिला अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह, संभाग अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, राजेंद्र सिंह, शालिनी शर्मा ने किया। इस मौके पर ममता शर्मा,गिरीश

कानूनगो, हेमंत व्यास, राजेंद्र सिंह, चंदा खत्री, अशोक शर्मा, देवेंद्र साहू, सुधीर वर्मा,रामकिशोर लोवंशी,संजय जोशी, विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सिंगर पीहू हासन ने किया।

लड़की को किडनैप कर ले जा रहे थे, ट्रैफिक जवान को इशारा कर खुद को ऐसे बचाया...

शहर में रविवार को यातायात पुलिस की सतर्कता से अनहोनी बच गई। रिंग रोड पर शाम को बाइक सवार दो मनचलों ने बस का इंतजार कर रही नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। पता चलने पर फिल्मी स्टाइल में यातायात पुलिस ने दोनों बदमाशों से लड़की को सकुशल छुड़ा लिया। घटना रविवार शाम 6:30 बजे खजराना चौराहे की है। एक बाइक तेज रफ्तार से बंगाली चौराहे की तरफ निकली। जिस पर दो युवकों के बीच में 15 साल की लड़की बैठी हुई थी। वहां यातायात संभाल रहे आरक्षक विजय जाटवाल की नजर बाइक पर पड़ीं। नजरें मिलने पर लड़की ने यातायात पुलिस से इशारों में मदद मांगी। यह देख विजय ने सूबेदार बृजराज अजनार को पूरी बात बताई। इतना सुनते ही सूबेदार ने बाइक दौड़ा दी और बंगाली ब्रिज कट के पास बाइक सवारों को रोक लिया।

जबरदस्ती बाइक पर बैठाया, मोबाइल भी छीना :सूबेदार को देखते ही बाइक रोक दोनों युवक भागने लगे। कुछ दूर दौड़ने के बाद सूबेदार और आरक्षक ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दोनों युवक अपना नाम पता बताने को तैयार नहीं थे। लड़की से पूछने पर बताया कि वह बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक युवक आया और बोला कि बहन यहां मत खड़े रहो। मैं

तुमको आगे छोड़ देता हूं। मैं गाड़ी के पास आई, तब तक एक और युवक आया और मुझे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और मेरा फोन भी छीन लिया था। **राहगीरों ने की पिटाई** :घटना के बाद पकड़े जाने पर मौजूद भीड़ ने भी दोनों युवकों की पिटाई शुरू कर दी। बाद में सूबेदार ब्रजराज अजनार, आरक्षक विजय और आरक्षक उधम सिंह, आरक्षक ब्रज भूषण ने दोनों बदमाशों को खजराना पुलिस चौकी लेकर पहुंचे और पुलिस के हवाले कर दिया।

शून्य कचरा दिवस...

कचरा सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, जीवनशैली में बदलाव जरूरी

ग्रामीण इलाकों तक उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के कारण प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन दर में कई गुना वृद्धि हुई ग्रामीण इलाकों तक उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के कारण प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन दर में कई गुना वृद्धि हुई

संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर 30 मार्च को पूरी दुनिया में शून्य कचरा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। विश्व के बहुत से देशों ने कचरे से निजात पाने का संकल्प लिया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि कचरे की मात्रा कम होने के बजाय निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि वर्तमान में उत्पन्न कचरे की मात्रा का आकलन किया जाए, तो वह इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की 25 परिधि बन जाए या चंद्रमा तक आने-जाने का सफर पूरा हो जाए। कचरे के पैदा होने और कुप्रबंधन से जल, थल और नभ प्रदूषित होते हैं, नतीजतन मानव सभ्यता पर इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई कदम उठाए गए। लेकिन प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन की दर में वृद्धि ही हुई है। वर्तमान संदर्भ में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण की दर विगत 10 वर्षों में बढ़ी है, लेकिन अब भी बड़ी आबादी, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कचरा प्रबंधन की गतिविधियों से कोसों दूर हैं।

सुदूर ग्रामीण इलाकों तक उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के कारण प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन दर में कई गुना वृद्धि हुई है। पहले यह माना जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर ही कचरे का निस्तारण हो जाता है, क्योंकि उसमें अधिकांश भाग जैविक कचरे का होता था। लेकिन अब प्लास्टिक, कागज, पैकेजिंग इत्यादि ने आम ग्रामीणों के जीवन में जगह बना ली है, जिससे कचरे की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।

अगले कुछ वर्षों में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले देश में कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यदि कचरा उत्पादन की यही गति जारी रही, तो वर्ष 2050 तक नियंत्रित एवं अनियंत्रित कचरे की मात्रा वर्ष 2020 की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो जाएगी और उसके निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना मुश्किल होगा, जिससे आबादी बुरी तरह प्रभावित होगी। कचरे की बढ़ी हुई मात्रा के निस्तारण के लिए भूमि संसाधन भी अपर्याप्त होंगे। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है कि प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन को कम किया जाए। दुर्भाग्यवश अभी तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। वर्तमान प्रयास कचरा संग्रहण, पृथक्कीकरण एवं निस्तारण तक ही सीमित हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद लगभग दो तिहाई कचरे का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण नहीं हो पाता है। खुले में कचरा फेंक देने से जहां प्रदूषण एवं बीमारियां बढ़ने का डर रहता है, वहीं कचरे में आग लगने की घटनाएं भी देखी जाती हैं। कचरा संपूर्ण जैविक संपदा एवं जीवन के लिए अभिशाप है। अनियंत्रित रूप से कचरे के निस्तारण से उनमें उपस्थित विषैले रसायन मिट्टी एवं पानी को अनुपयोगी बना देते हैं।

आईएमडी ने जारी की चेतावनी

अगले 3 महीने जमकर सितम ढाएगी गर्मी, लू के थपेड़े बढ़ाएंगे मुसीबत...

अप्रैल से लेकर जून माह तक मौसमी अपडेट को लेकर आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अप्रैल से लेकर जून महीनें के दौरान मैदानी इलाके के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है। जहां एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व आम चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मौसमी अपडेट जारी किया है। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अप्रैल से लेकर जून महीनें के दौरान मैदानी इलाके के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है। गौरतलब है कि इस समय पूरे देश में सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे।

अप्रैल-जून माह में होगी भीषण गर्मी- मौसम विभाग

मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में अप्रैल से लेकर जून के बीच भीषण गर्मी होने की आशंका है, इस दौरान तकरीबन 10 से 20 दिनों तक लू चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में तापमान को लेकर भी बदलाव दिख सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, अप्रैल से जून की अवधि के दौरान गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, एमपी, ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में लू का सबसे बुरा असर देखने को मिल सकता है।

भारत के कई हिस्सों में होगी भीषण गर्मी- मौसम विभाग

मौसम विभाग के मुताबिक, अप्रैल और जून के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। वहीं, अप्रैल में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, मध्य दक्षिण भारत में इसकी ज्यादा संभावना है। ईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक, इन क्षेत्रों में सामान्यतः एक से तीन दिनों की तुलना में दो से आठ दिनों तक लू चलने की आशंका है। भारत में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में होंगे।

मनरेगा के तहत काम की बढ़ी मांग... क्या गांवों में रोजगार की दिक्कत हो रही है?

मनरेगा योजना के तहत दिए गए काम के दिनों की संख्या कोरोना महामारी से पहले के समय (2019-20) से 40 करोड़ ज्यादा हो गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि गांवों में अभी भी आर्थिक दिक्कतें हैं और शहरों में रोजगार के अवसर पूरी तरह वापस नहीं आए हैं। मनरेगा योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार देने वाली मुख्य सरकारी योजना माना जाता है। 31 मार्च 2024 तक इस योजना के तहत दिए गए काम के दिनों की संख्या 305.2 करोड़ हो गई है। हालांकि यह आंकड़ा महीने के अंत तक का है और अंतिम संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसकी तुलना में 2022-23 में दिए गए काम के दिन 293.7 करोड़ रहे थे। यानी इस साल 12 करोड़ ज़्यादा दिनों का काम दिया गया।

कोरोना के बाद अभी तक रोजगार के अवसर नहीं आए वापस : 2023-24 में काम के दिन कम होने की उम्मीद थी क्योंकि 2022-23 कोविड महामारी के बाद का पहला साल था। माना जा रहा था कि कोरोना की दो बड़ी लहरों की वजह से रोजगार के अवसर अभी पूरी तरह से वापस नहीं आए हैं। लेकिन, उम्मीद के उलट काम के दिन कम होने के बजाय 12 करोड़ ज्यादा हो गए और अंतिम आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि, मनरेगा योजना को अक्सर गरीबों के लिए नाली खोदने जैसा काम बताया जाता है। लेकिन यह योजना असल में यह दिखाती है कि बिना किसी हुनर वाले मजदूरों के लिए आखिर में काम का असली सहारा क्या है। 2019-20, महामारी से पहले का साल, मनरेगा के तहत काम की मांग का असली रुझान दर्शाता है।

इस साल झमाझम बरसेंगे बदरा

देश के मध्य और पश्चिमी भाग में सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद...

मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट ने मंगलवार को बताया कि इस साल जून से सितंबर तक चार महीने के मानसून सीजन में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 102 फीसदी यानी 868.6 मिमी बारिश होगी, जो सामान्य की श्रेणी में है। देश के कई हिस्सों में भले ही मार्च-अप्रैल से ही सूरज की तपिश महसूस की जा रही हो, पर मानसून के मौसम में झमाझम बारिश के आसार हैं। इस साल लगभग पूरे देश में बादल जमकर बरसेंगे और मानसून सामान्य रहेगा।

मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट ने मंगलवार को बताया कि इस साल जून से सितंबर तक चार महीने के मानसून सीजन में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 102 फीसदी यानी 868.6 मिमी बारिश होगी, जो सामान्य की श्रेणी में है। स्काईमेट के मुताबिक, इन चार महीनों के दौरान देश के मध्य और पश्चिमी भाग में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में सामान्य बारिश होगी। 'मानसून पूर्वानुमान 2024' रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अनुकूल वर्षा दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे मुख्य मानसून वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी पर्याप्त बारिश होने की उम्मीद है।

पूर्वी राज्यों में कम बारिश की आशंका : स्काईमेट के मुताबिक, मानसून के चरम महीने में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी भारत के राज्यों में कम बारिश होने की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत में सीजन की पहली छमाही में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। लेकिन केरल, कोंकण, कर्नाटक और गोवा में सामान्य से अधिक और मध्य हिस्से में सामान्य बारिश होने का अनुमान है।

मजबूत ला नीना से बेहतरी की उम्मीद

स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह ने बताया कि सुपर अल नीनो से मजबूत ला नीना तक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव से मानसून की स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अल नीनो जाते-जाते मानसून सीजन के प्रारंभिक चरण को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान कुछ कम बारिश हो सकती है, पर इसकी भरपाई सीजन के दूसरे भाग में झमाझम बरसात से हो जाएगी। भारत में अल नीनो के प्रभाव से कम बारिश होती है और ला नीना के प्रभाव से अधिक। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में सबसे अधिक बारिश होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मासिक पैमाने पर जून में एलपीए का 95 प्रतिशत, जुलाई में 105 प्रतिशत, अगस्त में 98 प्रतिशत और सितंबर में 110 प्रतिशत बरसात होने का अनुमान है। बदलती जलवायु परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद रिपोर्ट में सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की गई है।

आरबीआई इस बार भी नीतिगत दर को रख सकता है यथावत : विशेषज्ञ

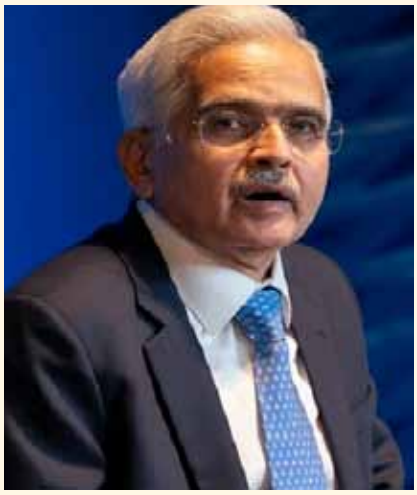

भारतीय रिजर्व बैंक इस सप्ताह पेश मौद्रिक नीति समीक्षा एक बार फिर नीतिगत दर को यथावत रख सकता हैं। इसका कारण आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंता दूर होने और इसके करीब आठ प्रतिशत रहने के साथ केंद्रीय बैंक का अब और अधिक जोर मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के लक्ष्य पर लाने पर हो सकता है। विशेषज्ञों ने यह बात कही। साथ ही नीतिगत दर पर निर्णय लेने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों के रुख पर गौर कर सकती है।

ये केंद्रीय बैंक नीतिगत दर में कटौती को लेकर स्पष्ट रूप से 'देखो और इंतजार करो' का रुख अपना रहे हैं। विकसित देशों में स्विट्जरलैंड पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने नीतिगत दर में कटौती की है। वहीं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान आठ साल बाद नकारात्मक ब्याज दर की स्थिति को समाप्त किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक तीन अप्रैल को शुरू होगी। मौद्रिक नीति समीक्षा की की घोषणा पांच अप्रैल को की जाएगी। यह वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा होगी। एक अप्रैल, 2024 से शुरू वित्त वर्ष में एमपीसी की छठ बैठकें होगी। आरबीआई ने पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो दर बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था। उसके बाद लगातार छह द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में इसे यथावत रखा गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, ''मुद्रास्फीति अभी भी पांच प्रतिशत के दायरे में है और खाद्य मुद्रास्फीति के मोर्चे पर भविष्य में झटका लगने की आशंका है, इसको देखते हुए एमपीसी इस बार भी नीतिगत दर और रुख पर यथास्थिति बनाए रख सकता है।'' उन्होंने कहा कि जीडीपी अनुमान में संशोधन हो सकता है। इस पर सबकी बेसब्री से नजर होगी। सबनवीस ने कहा, ''वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि उम्मीद से कहीं बेहतर रही है और इसीलिए केंद्रीय बैंक को इस मामले में चिंताएं कम होंगी और वह मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने पर ज्यादा ध्यान देना जारी रखेगा।

कोचिंग राष्ट्र बनने की दिशा में देश

नौकरियों को पुनर्जीवित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023, ग्रामीण भारत के 14 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं के बीच शिक्षा के निराशाजनक परिदृश्य पर रोशनी डालती है। पढ़ने के कौशल में आठवीं कक्षा के 30 फीसदी ग्रामीण छात्र दूसरी कक्षा के मानक पाठ नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अंकगणित कौशल में आठवीं कक्षा के 55 फीसदी ग्रामीण छात्र बुनियादी भाग करने में असमर्थ थे। जबकि अंग्रेजी समझ एवं कौशल में, आठवीं कक्षा के आधे ग्रामीण छात्र आसान वाक्यों को पढ़ने में असमर्थ थे और जो पढ़ सकते थे, उनमें से लगभग एक तिहाई छात्र अर्थ बताने में असमर्थ थे।

स्कूली शिक्षा में सीखने के अपर्याप्त परिणामों को देखते हुए समकालीन भारत में कोचिंग संस्थानों का विस्तार होना स्वाभाविक है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 ने बताया कि कक्षा एक से आठवीं तक के 30.5 फीसदी ग्रामीण छात्र सशुल्क निजी कोचिंग कक्षाएं ले रहे थे। स्कूली शिक्षा में मूलभूत कौशल और गहन सोच कौशल की कमी के कारण निजी कोचिंग पर निर्भरता जरूरी हो गई है। जैसे-जैसे छात्र उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कोचिंग पर निर्भरता बढ़ती जाती है। भारत एक कोचिंग राष्ट्र में बदल गया है, न केवल महानगरीय शहरों में, बल्कि छोटे शहरों में भी।

सरकारी नौकरियों की इच्छा, जो सामाजिक सुरक्षा के साथ आती है, शायद ग्रामीण छात्रों को आगे बढ़ने के लिए यही एकमात्र रास्ता हो। भारत के 91 फीसदी कार्यबल अनौपचारिक रोजगार में है, जिसे सामाजिक बीमा के बिना रोजगार के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात वृद्धावस्था पेंशन, मृत्यु/विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ इत्यादि से वंचित रोजगार।

वर्ष 2022-23 में स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर 13.4 फीसदी और स्नातकोत्तर और उससे ऊपर के लोगों के लिए 12.1 फीसदी रही, जो राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर 3.2 फीसदी (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) से लगभग चार गुना है।

भारत में बेरोजगारी की स्थिति एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा बनी हुई है। अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो छात्र कहां जाएंगे? वर्ष 2017-18 से 2022-23 की अवधि में कृषि क्षेत्र में छह करोड़ श्रमिकों की वृद्धि हुई है! आखिरी पीएलएफएस जुलाई, 2022 और जून, 2023 के बीच भी 80 लाख श्रमिकों को कृषि में जोड़ा गया था। निजी नौकरियों में रोजगार की अनिश्चितता को देखते हुए यह उनकी मजबूरी ही थी।

अधिकांश सरकारी नौकरियों के लिए भी परीक्षा में अंग्रेजी कौशल मुख्य घटकों में से एक है। जबकि आबादी की मुख्य भाषा और स्कूली शिक्षा का माध्यम हिंदी बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अंग्रेजी कौशल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कोचिंग अपरिहार्य हो जाती है।

माता-पिता की उम्मीदें ऊंची बनी हुई हैं और उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। सफलता और विफलता को परिभाषित करने में कोचिंग एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है।

सभ्य गैर-कृषि रोजगार की अनुपलब्धता, रुकी हुई सरकारी नौकरियां और सीमित सरकारी नौकरियों के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए युवाओं के बीच अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा है, जिसने छात्रों को ट्यूशन और कोचिंग में धकेल दिया है। कुल मिलाकर, शिक्षा का मौलिक अधिकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार में तब्दील नहीं हुआ है, इसलिए निजी ट्यूशन और कोचिंग संस्थान तेजी से बढ़ रहे हैं।

कोचिंग संस्थान लंबे समय तक एक अनियमित बाजार बने रहे, और कई शिकायतों और छात्रों की आत्महत्याओं के बाद ही सरकार कोचिंग सेंटरों को संचालित करने के लिए दिशा-निर्देश लेकर आई है। 'कोचिंग सेंटर का पंजीकरण और विनियमन, 2024' दिशा-निर्देश कोचिंग सेंटरों को भ्रामक वादे करने या सफलता की गारंटी देने से रोकते हैं। हालांकि, इसका उपाय स्कूली शिक्षा, उच्च अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव में सीखने के परिणामों में सुधार करना है। इसके अलावा, हर कोई कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता और सरकारी नौकरी की आकांक्षा नहीं कर सकता। गैर-औद्योगिकीकरण और संरचनात्मक परिवर्तन के उलट होने की स्थिति में जो कुछ बचा है, वह है गिग इकनॉमी, जो बिना किसी सामाजिक सुरक्षा जाल के कार्यबल को केवल निर्वाह प्रदान करती है। इस प्रकार, समकालीन भारत में नौकरियों को पुनर्जीवित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

फैसलाबाद में डोर से युवक की मौत के बाद आक्रोश

मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पतंग बाजी को बताया खूनी खेल...

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पतंगबाजी पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पतंग उड़ान एक खूनी खेल हैं। इसके लिए कठोर कानून बनाने का समय आ गया है। गौरतलब है कि उनका यह बयान फैसलाबाद की घटना के बाद सामने आया जब बाइक चालक की पतंग की डोर से गला कटने से मौत हो गई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा कि फैसलाबाद में एक होनहार युवक की पतंग की डोर के चलते मौत हो गई। मैं सभी प्रशासनिक और पुलिस विभागों को छापेमारी करने और ऐसे उल्लंघनों में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दे रही हूं। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्होंने लिखा, मैं अधिकारियों को 48 घंटे का समय दे रही हूं।

फैसलाबाद की घटना के बाद से ही मरियम नवाज खासा आक्रोशित दिखाई दे रही है। उन्होंने पतंगबाजी को रोकने में अधिकारियों की विफलता पर चिंता जाहिर की है। मौज मस्ती के लिए किसी नागरिक की जान जोखिम में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस बीच, पुलिस अधिकारी कैप्टन मुहम्मद अली जिया ने अपने क्षेत्र में पतंगबाजी रोकने में विफल रहने के लिए

फैक्ट्री एरिया स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को निलंबित कर दिया।

बता दें फैसलाबाद का रहने वाला 20 वर्षीय आसिफ शफीक पतंग की डोर की चपेट में आ गया, जिसके कारण गले पर गंभीर घाव बन गए। घटना के बाद आसिफ की मौत हो गई। गौरतलब है कि पतंग की डोर के कारण लगातार मौतों में वृद्धि के बाद 2005 से पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि फैसलाबाद समेत पंजाब में कुछ शहर हैं, जहां प्रतिबंध के बावजूद बसंत उत्सव मनाया जाता है। पंजाब पुलिस ने हाल ही में लाहौर और प्रांत के अन्य हिस्सों में पतंग उड़ाने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

न्यायाधीश की बेटी पर पोस्ट कर फंसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

सहायक जिला अटॉर्नी जोशुआ स्टींगलास ने मर्चन को लिखे एक पत्र में तर्क दिया कि अदालत के कर्मचारियों या उनके परिवारों को परेशान करने वाले बयानों पर प्रतिबंध लगाने से ट्रंप की बयानबाजी बंद हो सकती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वह कई मुकदमे में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इस बार हश-मनी मामले में डोनॉल्ड ट्रंप मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल, मैनहट्टन अभियोजकों ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि ट्रंप ने हाल ही में न्यायाधीश की बेटी पर हमला करके और सोशल मीडिया पर उसके बारे में झूठा दावा करके एक गैग आदेश का उल्लंघन किया हैं।

गैग आदेश के दायरे को स्पष्ट करें : न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन ने मंगलवार को जांच का एक आदेश जारी किया था। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति को अदालत से जुड़े कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों पर हमलों से तुरंत बचने का निर्देश दिया गया था।अब मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय ने गैग आदेश के दायरे को स्पष्ट करने के लिए

कहा है।

सजा दी जानी चाहिए : सहायक जिला अटॉर्नी जोशुआ स्टींगलास ने मर्चन को लिखे एक पत्र में तर्क दिया कि अदालत के कर्मचारियों या उनके परिवारों को परेशान करने वाले बयानों पर प्रतिबंध लगाने से ट्रंप की बयानबाजी बंद हो सकती है।उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप अगर आगे उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए।

ट्रंप के वकीलों का यह तर्क : इस पर ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया कि जिला अटॉर्नी का कार्यालय आदेश की गलत व्याख्या कर रहा है। यह आदेश उन्हें एक राजनीतिक सलाहकार लॉरेन मर्चन के बारे में टिप्पणी करने से नहीं रोकता है। बता दें, लॉरेन ने ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रपति जो बाइडन और अन्य डेमोक्रेट के लिए अभियानों पर काम किया है।

ट्रंप के वकील टॉड ब्लैंच और सुसान नेशेल्स ने अभियोजन पक्ष के पत्र के जवाब में मर्चन को लिखा, 'अदालत राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा कुछ करने का निर्देश नहीं दे सकती, जहां गैग आदेश की जरूरत नहीं है। गैग ऑर्डर के अर्थ को स्पष्ट या पुष्टि करने के लिए जिस तरह से लोग सुझाव देते हैं, उसका विस्तार करना होगा।

हाईकोर्ट का आदेश

संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे की जांच करेगी सीबीआई

सीबीआई संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार और स्थानीय लोगों की जमीन को कब्जाने के आरोपों की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना को लेकर खूब हंगामा हुआ था। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच भी सीबीआई द्वारा ही की जा रही है। संदेशखाली मामले में भी टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर आरोप हैं। शाहजहां शेख ईडी टीम पर हमले का भी आरोपी है। अपने आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्ट की निगरानी में संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध, जमीन कब्जाने जैसे आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। बीते गुरुवार को उच्च न्यायालय ने संदेशखाली की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने संदेशखाली में हिंसा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला बेहद शर्मनाक है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। कोर्ट ने कहा था कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि 'यहां 100 फीसदी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ सरकार की है। अगर किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है तो सरकार जिम्मेदार है। अगर पीड़ित पक्ष की वकील जो भी कह रही हैं, उसमें एक फीसदी की भी सच्चाई है तो यह बेहद शर्मनाक है।'

क्या है संदेशखाली मामला

संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाए थे कि स्थानीय टीएमसी नेताओं ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप भी लगाए। इस मुद्दे पर बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया था। दरअसल संदेशखाली मामले का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख है। शाहजहां शेख ईडी टीम पर हमले का भी आरोपी है। साथ ही बंगाल के राशन घोटाले में भी उसका नाम है।

आरटीआई में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

ट्रेन चालकों के करीब 15 प्रतिशत पद खाली...

आरटीआई के तहत जारी आकंड़ों के मुताबिक, लोको पायलट के 70,093 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 14,429 (लगभग 20.5 प्रतिशत) रिक्त हैं, जबकि सहायक लोको पायलट के 57,551 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 4,337 (लगभग 7.5 प्रतिशत) रिक्त हैं। रेलवे में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कुल 1,27,644 पद हैं जिनमें से 18,766 पद (14.7 प्रतिशत) एक मार्च 2024 को रिक्त थे। रेलवे बोर्ड ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत जवाब में यह जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि सहायक लोको पायलट के मुकाबले लोको पायलट के अधिक पद खाली हैं।

'लोको पायलट पर काम का बढ़ रहा दवाब'

रेलवे के कई कर्मचारी संघों और लोको पायलट से जुड़े संघों ने कहा कि रिक्त पदों के चलते चालकों को अतिरिक्त घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें रिक्त पदों की भरपाई भी करनी होती है। ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि इससे लोको पायलट पर काम का दबाव और तनाव बढ़ रहा है, जो सुरक्षित ट्रेन परिचालन के हित में नहीं है।

मौजूदा लोको पायलटों को करना पड़ रहा ओवर टाइम

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन द्वारा मई 2023 में तैयार एक आधिकारिक नोट में कहा गया था कि लोको पायलट की कमी के कारण अप्रैल 2023 में 23.5 प्रतिशत लोको पायलट ने काम करने के अधिकतम समय 12 घंटे से अधिक काम किया।

जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने के लिए उठाएं कदम- पांधी

भारतीय रेलवे लोको रनिंगमैन संगठन (आईआरएलआरओ) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय पांधी ने कहा कि रिक्त पदों की संख्या आंकड़ों से अधिक हो सकती है क्योंकि लगभग दो से तीन प्रतिशत ड्राइवर आधिकारिक रिकॉर्ड में अपनी नौकरी की भूमिका बदले बिना कई कार्यालय में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन चालक तनाव में हैं और रेलवे को रिक्त पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए।

लोको पायलट- सहायक लोको पायलट के कई पद रिक्त

आरटीआई के तहत जारी आकंड़ों के मुताबिक, लोको पायलट के 70,093 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 14,429 (लगभग 20.5 प्रतिशत) रिक्त हैं, जबकि सहायक लोको पायलट के 57,551 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 4,337 (लगभग 7.5 प्रतिशत) रिक्त हैं। रेलवे बोर्ड ने मध्य प्रदेश के चंद्र शेखर गौड़ की अर्जी पर यह जानकारी दी। गौड़ ने बताया कि उन्होंने जोन-वार रिक्तियों की जानकारी मांगी थी, लेकिन बोर्ड ने कहा कि ऐसे आंकड़े केंद्रीयकृत नहीं हैं।

हिंद महासागर में सक्रिय होगा खास सिस्टम

भारत अमेरिका का बड़ा फैसला; मिलेगी मदद

भारत और अमेरिका द्वारा हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली (IndOOS) को फिर से सक्रिय करने का फैसला लिया गया है। इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम (IndOOS) एक खास तरह की प्रणाली है, जिसकी मदद से मौसम के पूर्वानुमान और वायुमंडलीय डाटा एकत्रित करने में आसानी होती है। यह सिस्टम 36 दलदली सतहों पर फैला एक तरह का नेटवर्क है, जिससे मौसम विज्ञानियों को पूर्वानुमान में काफी सहायता मिलती है। कोरोना महामारी के दौरान इस प्रणाली की अनदेखी की गई थी, जिस वजह से मौसम वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण डेटा हासिल करने में मुश्किल हो रही थी।

भारत-अमेरिका के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत

पिछले महीने पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन की अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अधिकारी रिक स्पिनराड के साथ एक बैठक हुई। इस दौरान हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली को फिर से सक्रिय करने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद रविचंद्रन ने कहा कि भारत और अमेरिका इसे फिर से सक्रिय करना चाहते हैं। उन्होंने मार्च में अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन (NOAA) प्रमुख के साथ इस पर चर्चा की थी। उनका कहना है कि एनओएए इसके लिए अपकरण प्रदान करने के लिए राजी हो गया है।

अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसायटी ने क्या कहा?

अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसायटी (बीएएमएस) ने एक लेख में बताया है कि कई देशों के मौसम वैज्ञानिकों ने लिखा है कि कोरोना महामारी की वजह से हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली की तैनाती और रखरखाव को बाधित किया है। इस वजह से उपकरणों की खरीद और नवीनीकरण पर ध्यान देना जरूरी है। लेख में आगे बताया गया है कि इस सिस्टम के उपकरण साल में एक बार बदले जाते हैं क्योंकि इसके सेंसर काम करना बंद कर देते हैं और बैटरियां खत्म हो जाती हैं। इनकी मरम्मत आम तौर पर इंडोनेशिया, भारत और दक्षिण कोरिया के अनुसंधान जहाजों का उपयोग करके की जाती है।

बताया गया है कि चक्रवात की चेतावनी, तूफान की चेतावनी, मानसून की भविष्यवाणी और जलवायु पूर्वानुमान के लिए इस प्रणाली (IndOOS) का परिचालन और अवलोकन आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सोशल मीडिया का दुरुपयोग यह न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में सोशल मीडिया पर न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में पोस्ट की जा रही हैं। अदालत ने इसे न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कहा है। लंबित और विचाराधीन मामलों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से संदेश और लेख प्रसारित किए जा रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने असम के विधायक करीम उद्दीन बरभुइया के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करते हुए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। बता दें कि विधायक को शीर्ष अदालत में फैसले के लिए आरक्षित एक मामले के संबंध में भ्रामक फेसबुक पोस्ट के लिए अवमानना नोटिस जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में सोशल मीडिया पर टिप्पणियां और लेख पोस्ट किए जा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही हमारे कंधे किसी भी दोष या आलोचना को सहन करने के लिए काफी चौड़े हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में सोशल मीडिया के माध्यम से न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में पोस्ट की जा रही हैं, जो न्यायपालिका को कमजोर करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि न्यायालयों की न्याय प्रक्रिया में इस तरह के हस्तक्षेप पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

पीठ ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) विधायक को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले को अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। विधायक को कार्यवाही के दौरान कोर्ट में पेश होने का भी निर्देश दिया गया है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने शीर्ष अदालत में फैसले के लिए आरक्षित एक मामले के संबंध में भ्रामक फेसबुक पोस्ट की है।

देश में जो हालात हैं, उनसे एक बार फिर देश टूट सकता है

इमरान का संदेश देते हुए बैरिस्टर राजा ने कहा कि '1970 में तत्कालीन सेना प्रमुख याहया खान चाहते थे कि किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले, लेकिन जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला तो सेना ने बहुमत छीन लिया क्योंकि याहया खान को राष्ट्रपति बनना था।' पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने चेतावनी दी है कि देश में जो मौजूदा हालात हैं, उनसे एक बार फिर ढाका जैसी त्रासदी हो सकती है। इमरान खान ने साल 1971 के हालात की मौजूदा हालात से तुलना की और कहा कि देश आर्थिक तौर पर तबाही के कगार पर पहुंच सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान ने रावलपिंडी की अडियाला जेल से देशवासियों और पार्टी समर्थकों के लिए संदेश जारी किया। अपने संदेश में इमरान खान ने कहा कि कोई भी देश या संस्थान बिना आर्थिक स्थिरता के नहीं चल सकता। पीटीआई के मुख्य सूचना सचिव रऊफ हसन ने मीडिया से बात करते हुए इमरान खान के संदेश की जानकारी दी। वहीं पार्टी के नेता बैरिस्टर राजा ने बताया कि इमरान खान अभी भी देश के लिए समर्पित हैं, लेकिन देशवासियों के लिए चिंतित भी हैं। राजा ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि जब लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, तभी अर्थव्यवस्था विकास करेगी।

इमरान का संदेश देते हुए बैरिस्टर राजा ने कहा कि '1970 में तत्कालीन सेना प्रमुख याहया खान चाहते थे कि किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले, लेकिन जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला तो सेना ने बहुमत छीन लिया क्योंकि याहया खान को राष्ट्रपति बनना था।' हमुदूर रहमान आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि 'हम फिर से वही गलती कर रहे हैं। 1970 में भी लंदन प्लान था और अब एक बार फिर लंदन प्लान के तहत सरकार थोप दी गई है।' इमरान खान और उनकी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में धांधली हुई और जनादेश की चोरी की गई। पीटीआई ने इसके आरोप पाकिस्तानी सेना पर लगाए हैं।

संयुक्त राष्ट्र में लहराया भारत का परचम, WNCB सहित महत्वपूर्ण आयोगों में सर्वाधिक मतों से जीता

भारत को ईसीओएसओसी के मतदान करने वाले 53 सदस्यों में से 41 के वोट मिले, जो सभी विजेता सदस्य देशों में सबसे अधिक हैं। पावडिया ने 41 वोट के साथ कठिन चुनाव में शानदार जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 30 वोट मिले।

अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) नियंत्रण बोर्ड समेत संयुक्त राष्ट्र के कई प्रमुख निकायों के लिए भारत के चयन के साथ देश का परचम बुलंद हुआ है। भारत की जगजीत पवाडिया गुप्त मतदान के जरिये मार्च 2025 से 2030 तक बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुई हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक-सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में सर्वाधिक मत मिले हैं।

अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) में भारत को 2025 से 2029 तक के लिए 'कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन' (महिलाओं की स्थिति पर आयोग) के लिए भी चुना गया। 2025-2027 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड, 2025-2027 के लिए परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के कार्यकारी बोर्ड में भी भारत को चुना गया है।

भारत को 53 में से 41 वोट

भारत को ईसीओएसओसी के मतदान करने वाले 53 सदस्यों में से 41 के वोट मिले, जो सभी विजेता सदस्य देशों में सबसे अधिक हैं। पावडिया ने 41 वोट के साथ कठिन चुनाव में शानदार जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 30 वोट मिले। बोर्ड की पांच सीट के लिए 24 उम्मीदवार थे, जिस कारण चुनाव अत्यधिक प्रतिस्पर्धी था।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) ने अपने 17 सहायक निकायों में रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव कराए थे। भारत ने 2025-2030 के लिए आईएनसीबी का प्रतिष्ठित चुनाव दोबारा जीता और कई प्रमुख संयुक्त राष्ट्र निकायों में सीट हासिल कीं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी 'एक्स' पर जीत की पुष्टि करते हुए कहा, भारत ने बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्य देशों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किए। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विदेश मंत्रालय की टीम की सराहना की और कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया।

वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने 'एक्स' पर लिखा, भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' (दुनिया एक परिवार) के सिद्धांत के साथ संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। उन्होंने कहा, यह दर्शन वैश्विक विचार-विमर्श में रचनात्मक योगदान देने, एकता की भावना को बढ़ावा देने व साझा जिम्मेदारी के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करता है।

2015 से बोर्ड सदस्य हैं पावडिया

पावडिया 2015 से अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड की सदस्य हैं। उन्हें मई 2019 में 2020 से 2025 के पांच साल के कार्यकाल के लिए परिषद द्वारा फिर से चुना गया था। उन्होंने 2021 से 2022 तक बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।

युद्ध के कारण इस्राइली निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की हुई कमी

भारत से 6000 श्रमिक जाएंगे इस्राइल

जी2जी समझौते के तहत 6000 श्रमिकों को इस्राइल लाया जा रहा है। पिछले मंगलवार को भारत से 64 श्रमिक इस्राइल पहुंचे थे। उम्मीद है कि अप्रैल के मध्य तक कुल 850 श्रमिक इस्राइल पहुंच जाएंगे।

इस्राइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में इस्राइल के निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की कमी हो गई है, जिस वजह से अप्रैल और मई में भारत से छह हजार मजदूर इस्राइल जाएंगे। इस्राइल सरकार ने बुधवार देर रात बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि इस्राइली प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वित्त मंत्रालय और निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा चार्टर उड़ानों पर सब्सिडी देने के संयुक्त निर्णय के बाद श्रमिकों को एयर शटल से इस्राइल लाने के फैसले पर मुहर लगी है।

फलस्तीन के 97,000 श्रमिक इस्राइल में करते थे काम

गौरतलब है कि इस्राइली निर्माण उद्योग उन विशिष्ट क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देता है, जहां इस्राइली श्रमिकों की कमी होती है। युद्ध से पहले इस्राइल में 80,000 श्रमिक वेस्ट बैंक से तो वहीं 17,000 श्रमिक गाजा पट्टी से आए थे लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से अधिकांश श्रमिकों का वर्क परमिट रद्द कर दिया गया है। बता दें, युद्ध के कारण देश में श्रमिकों की भारी कमी हो गई, जिस वजह से कई परियोजनाएं रुक गई। इस वजह से लोगों को जीवनयापन करने में भी दिक्कत होने लगी।

अप्रैल मध्य तक 850 श्रमिक पहुंच जाएंगे इस्राइल

बयान के अनुसार, जी2जी समझौते के तहत 6000 श्रमिकों को इस्राइल लाया जा रहा है। पिछले मंगलवार को भारत से 64 श्रमिक इस्राइल पहुंचे थे। उम्मीद है कि अप्रैल के मध्य तक कुल 850 श्रमिक इस्राइल पहुंच जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि इस्राइल आने वाले अधिकांश चयनित श्रमिकों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया है और इस्राइल आने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के अलावा, करीब 7,000 श्रमिक चीन से तो वहीं 6,000 श्रमिक पूर्वी यूरोप से आ रहे हैं।

भारतीय राजदूत ने इस्राइली श्रममंत्री से की मुलाकात

इस्राइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने बुधवार को देश के श्रम मंत्री, योव बेन-त्जूर से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत की और भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा व भलाई का मुद्दा भी उठाया। बैठक के दौरान, उन्हें वहां भारतीय श्रमिकों के कल्याण के लिए इस्राइली मंत्रालय की प्रवर्तन गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दी गई।

इस्राइल में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, बैठक के दौरान सिंगला को इस्राइल में भारतीय श्रमिकों के अधिकारों व कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की प्रवर्तन गतिविधियों जानकारी दी गई। पिछले हफ्ते भारतीयों का पहला जत्था जी2जी समझौते के तहत इस्राइल गया पहुंचा है। भारत ने इस्राइली अधिकारियों से उनकी सुरक्षा को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। साल की शुरुआत में, इस्राइल में 10,000 से अधिक भारतीय निर्माण श्रमिकों को भर्ती का अभियान हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। इस समय करीब 18,000 भारतीय कामगार इस्राइल में हैं।

इस्राइली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से की थी बात

इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पिछले साल दिसंबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बात की थी। इस दौरान श्रमिकों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। इस्राइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत ने पिछले साल अप्रैल में भारत यात्रा के दौरान भारतीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी और श्रमिकों के मुद्दे पर चर्चा की थी।

ऑपरेशन 'ऑल आउट' में CRPF को मिला 'फ्री' हैंड, रॉकेट से बमबारी

3 साल में खत्म हो जाएंगे नक्सली

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी ने आरोप लगाया है कि सात अप्रैल को सुरक्षा बलों द्वारा ग्रामीण इलाकों में रॉकेट से बमबारी की जा रही है। ड्रोन से हवाई हमले किए जा रहे हैं। इसके चलते लोगों में भय और डर का माहौल बना हुआ है।

केंद्र सरकार ने नक्सलियों/माओवादियों का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों को 'फ्री' हैंड दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि तीन साल में कोई भी नक्सली नहीं बचेगा। चाहे किसी भी राज्य में नक्सली हों, इस अवधि में उन्हें खत्म किया जाएगा। ऐसे में संभव है कि आने वाले समय में सैकड़ों नक्सली, सुरक्षा बलों के समक्ष सरेंडर करते हुए दिखाई दें।

विशेषकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आए दिन फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस 'एफओबी' स्थापित किए जा रहे हैं। नतीजा, नक्सली अपने पुराने ठिकाने छोड़कर घने जंगल की तरफ भागने लगे हैं। दूसरी तरफ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी ने आरोप लगाया है कि सात अप्रैल को सुरक्षा बलों द्वारा ग्रामीण इलाकों में रॉकेट से बमबारी की जा रही है। ड्रोन से हवाई हमले किए जा रहे हैं। इसके चलते लोगों में भय और डर का माहौल बना हुआ है।

तीस मिनट तक रॉकेट लांचरों से भीषण बमबारी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी का दावा है कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण बस्तर के पामेड़ इलाके में सात अप्रैल को रॉकेट से बमबारी की है। कमेटी ने कड़े शब्दों में इस बमबारी की निंदा की है। कमेटी के मुताबिक, सात अप्रैल को बीजापुर-सुकमा जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र, पालागुड़ा, इत्तागुड़ा, जिलोरगड्डा, गोम्मगुड़ा व कंचाल आदि गांवों और जंगलों में रात पौने 12 बजे, करीब तीस मिनट तक रॉकेट लांचरों से भीषण बमबारी की गई। गांव और जंगल में रॉकेट लांचरों से 30 से अधिक हाई एक्सप्लोसिव बम दागे गए हैं। जहां पर ये बम गिरे हैं, वहां 100 से 200 वर्ग मीटर इलाके में पेड़-पौधे तथा जानवर नष्ट हो गए। लोगों ने इधर-उधर भागकर अपनी जान बचाई है। इससे पहले भी नक्सलियों द्वारा कई बार यह आरोप लगाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से बमबारी की जा रही है। अंधेरे में एयर स्ट्राइक की जाती है।

लोगों को उठाना पड़ रहा है आर्थिक नुकसान

दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी द्वारा अपने प्रेस बयान में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में भय और डर का माहौल बना हुआ है। इन दिनों जंगल और खेतों में महुआ बिनने का काम जोरों पर है। यही आदिवासियों की आय का प्रमुख स्रोत है। महुआ के फूल को जंगली जानवरों द्वारा खाने से बचाने के लिए लोग, दिन रात पेड़ों के नीचे ही सो रहे हैं। इस तरह की बमबारी से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दक्षिण बस्तर डिविजन (बीजापुर सुकमा जिला) में गत चार माह में 11 फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस 'एफओबी' स्थापित किए गए हैं। बेस पर सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी आदि, बलों के जवान तैनात हैं। सभी कैंपों से हर दिन रॉकेट, 81 एमएम मोर्टार और ड्रोन के द्वारा बमबारी की जा रही है। दो तीन किलोमीटर की दूरी पर एक कैंप स्थापित कर दक्षिण बस्तर इलाके को पुलिस कैंप में तब्दील कर दिया गया है। कमेटी ने सुरक्षा बलों पर ज्यादती और अत्याचार करने का आरोप लगाया है। महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप भी लगाए गए हैं।

आखिरी प्रहार की तैयारी : देश के विभिन्न हिस्सों में फैले नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' और संबंधित राज्य की पुलिस फोर्स, इस राह पर आगे बढ़ चुके हैं। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की इस लड़ाई में सीआरपीएफ एवं इसकी विशेष प्रशिक्षित इकाई 'कोबरा' को कई अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा बलों ने जंगल, पहाड़, गांव और गुफाओं में दस्तक दी है। सीआरपीएफ जवानों ने हाल ही में सुकमा के किस्टाराम थाना क्षेत्र के डुब्बामरका एवं बीरम के जंगलों में स्थित एक गुफा में रखे गए विस्फोटकों एवं हथियारों का जखीरा पकड़ा है। गुफा में बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल), बीजीएल प्रोजेक्टर, जिलेटिन रॉड, इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटर और आईईडी बनाने का दूसरा सामान बरामद किया गया।

फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से खुल रही विकास की राह

नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थापित 31 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का फायदा, केवल सुरक्षा बलों को ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी मदद से उस इलाके में विकास की एक राह प्रशस्त होती है। सड़क, पुल, मोबाइल टावर और विकास के दूसरे कामों में तेजी आ जाती है। वहां रह रहे ग्रामीणों को यह भरोसा होता है कि अब सुरक्षा बलों ने इलाके की कमान संभाल ली है। उनके बच्चों को स्कूलों में जाने का अवसर मिलेगा। अगर उनके खेतों में नकदी फसलों की पैदावार होती है, तो उसे मंडी तक पहुंचाने की सुविधा मिल जाती है। जब तक वहां पर राज्य सरकार का स्वास्थ्य महकमा अपना केंद्र स्थापित नहीं करता, तब तक ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा बल के जवानों द्वारा मुहैया कराई जाती है।

कांग्रेस और भ्रष्टाचार के बीच अटूट रिश्ता- राजनाथ सिंह

भाजपा नेता ने कहा कि वैसे हमारी पार्टी यह चाहती है भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। इससे आपका समय बचेगा और देश के संसाधनों की भी बचत होती। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद समिति ने एक रिपोर्ट दी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी की तरह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारतीय राजनीति के 'सर्वश्रेष्ठ फिनिशर' हैं क्योंकि उनकी पार्टी की उपस्थिति हर जगह कम हो रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक चुनाव प्रचार रैली में बोलते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार के साथ 'अटूट' रिश्ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार के बीच एक अटूट रिश्ता है। एक गाना था 'तू चल मैं आई', कांग्रेस और भ्रष्टाचार का रिश्ता वैसा ही है। आपने देखा होगा जहां कांग्रेस आती है, वहां भ्रष्टाचार भी पहुंच जाता है। पार्टी का पतन हो रहा है।

राजनाथ ने सवाल करते हुए कहा कि क्रिकेट में प्रसिद्ध फ़िनिशर कौन है? एम एस धोनी; इसलिए, अगर कोई मुझसे पूछता है कि भारतीय राजनीति का शीर्ष फिनिशर कौन है, तो वह राहुल गांधी होंगे। उन्होंने कहा कि अभी

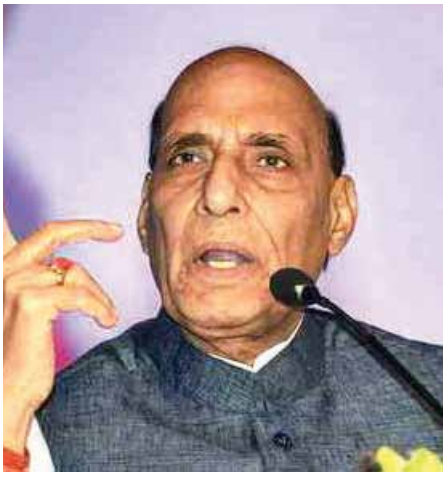

चार महीने पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें आप लोगों ने भाजपा की झोली भर दी और रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई दी है। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब कुछ लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे।मगर आपने स्पष्ट बहुमत की सरकार बना दी है।

भाजपा नेता ने कहा कि वैसे हमारी पार्टी यह चाहती है भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। इससे आपका समय बचेगा और देश के संसाधनों की भी बचत होती। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद समिति ने एक रिपोर्ट दी है। एक साथ चुनाव से लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि एक समय बीमारू राज्य जाना वाला मध्य प्रदेश आज भारत की ग्रोथ इंजन बन चुका है। आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से दौड़ रही है तो उसमें मध्य प्रदेश की भी अच्छी ख़ासी भूमिका है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि अब छोटे किसानों के लिए सरकार भंडारण से जुड़ी समस्या का समाधान देने का काम कर रही है। इस योजना पर सरकार सवा लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। इसके चलते छोटा किसान किसान भी अपनी उपज का भंडारण कर सकेगा और सही समय पर उसे बेच सकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में आये दिन आतंकवादी घटनायें होती थी। मुंबई में हुई आतंकी घटना कितनी बड़ी थी। पिछले दस वर्षों में देश में जम्मू एवं कश्मीर एवं एकाध अन्य स्थानों को छोड़ कर कहीं भी, कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है।

यूएन ने कहा- सार्वजनिक जीवन में अफगान महिलाओं की भागीदारी जरूरी, पीड़ितों में 90 फीसदी महिलाएं-बच्चे

संयुक्त राष्ट्र ने सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में अफगान महिलाओं को सशक्त, सार्थक व सक्रिय भागीदार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। संगठन ने कहा कि देश में लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में अफगान महिलाओं को सशक्त, सार्थक व सक्रिय भागीदार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान की समाचार एजेंसी खामा प्रेस ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) की उप-समन्वयक इंद्रिका रतवाट्टे ने लैंगिक समानता और अफगान महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी लैंगिक समानता और अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने पर जोर दिया। ओसीएचए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान में मदद वितरण के लिए जरूरी बजट का केवल छह फीसदी सुरक्षित किया जा सकता है।

रतवाट्टे ने बजट में कटौती पर गहरी चिंता जताई और अफगानिस्तान में लैंगिक समानता, महिलाओं और

लड़कियों के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के समर्थन पर जोर दिया। रतवाट्टे के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र का फोकस महिलाओंर और लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना है। प्रभावित लोगों में से 90 फीसदी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान में प्रस्तावित 3.03 अरब अमेरिकी डॉलर के बजट में से केवल 290 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही सुरक्षित किए गए हैं। खामा प्रेस के मुताबिक, इसमें आगे कहा गया है कि धन की कमीअफगानिस्तान में मदद वितरण के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगान लोगों के लिए वित्तीय मदद बढ़ाकर अपनी प्रतिबद्धता दोगुना करने का आग्रह किया है।

प्रदेश के होशंगाबाद में मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर किया जबरदस्त वार

आग देश में नहीं उनके दिलों में लगी है...

पीएम मोदी ने कहा, 'अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। आग देश में नहीं, बल्कि आग और जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जला रही है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 'एक बार फिर मोदी सरकार' का नारा दोहराते हुए कहा, 'अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया था और होशंगाबाद ने तो कमाल कर दिया था। यहां से जो लहर उठी थी, वो लहर पूरे देश में फैल चुकी है। आज देश के कोने-कोने से एक ही आवाज आ रही है - फिर एक बार मोदी सरकार।' संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को उनकी जयंती पर याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मजयंती है। उनकी जन्मस्थली महू यहां से ज्यादा दूर नहीं है। महू में उनका घर हो या देश-विदेश में वे जहां भी रहे, उन स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य भाजपा सरकार को मिला है। जो सम्मान कांग्रेस ने उनको कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा बाबा साहेब को अपमानित करने का ही काम किया है। बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है, उसके कारण ही आज गरीब मां का ये बेटा मोदी, आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'ये बाबा साहेब का संविधान है, जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है। जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति के रूप में पहली नागरिक है। हमने बाबा साहेब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत में उनके योगदान को नई पहचान दी है। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, उस डिजिटल पेमेंट योजना का नाम BHIM UPI है, ये नाम हमने बाबा साहेब के नाम पर ही रखा है।'

होशंगाबाद की चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी पत्तों के महल की तरह गिरा दिया। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा और जो मन किया वो लिखवाया और खुद का ही महिमामंडन करवाया। कांग्रेस की मानें तो लोकतंत्र तब ठीक चल रहा था, फलफूल रहा था। लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना वैसे ही कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र पर खतरा हो जाएगा। कांग्रेस वालों को पता नहीं है। ये बाबासाहेब का जो संविधान है, उसके कारण तो मोदी यहां पहुंचा है।'

अगर किसी राजनीतिक दल पर जनता का विश्वास है तो वह भाजपा है : भजनलाल

मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुएकहा, ''जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है.. युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया है... उनमें से एक को भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कहा कि मौजूदा समय में किसी भी राजनीतिक दल पर जनता का विश्वास नहीं रहा है और अगर किसी राजनीतिक दल पर जनता का विश्वास है तो वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''किसी भी राजनीतिक दल पर जनता का विश्वास नहीं रहा है, लेकिन अगर जनता का विश्वास किसी राजनीतिक दल पर है तो वो भाजपा है जिस पर जनता का विश्वास है। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश की जनता भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ देख रही है। कार्यकर्ता जनता के विश्वास को बनाये रखें और उसके दुख और दर्द में उसका सहयोग करें और हमारी योजनाओं का उन्हें लाभ दिलायें। शर्मा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी योजना) का सबसे ज्यादा लाभ भरतपुर को मिलेगा।भरतपुर के रूपवास में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी के पानी से पांचना बांध जुड़ेगा और वहां से डूंगरी बांध से दौसा होते हुए अलवर के बांध तथा सीकरी के बांध में भी पानी आयेगा और सीधा मोती झील को पानी पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना से पीने का पानी भी मिलेगा और दो लाख अस्सी हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होगी। उन्होंने कहा इससे कुम्हेर, डीग, नदबई, बयाना, रूपवास और घना अभयारण्य को भी उसका फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, जिसके मन में काम करने की तमन्ना हो.. जिसको यह एहसास होता है कि मुझे काम करना है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा बिजली में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार राज्य को 90 हजार करोड़ का घाटा देकर गई है। तीन साल बाद राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं बल्कि वह बिजली बेचने वाला होगा। इसलिये हम दो साल बिजली और पानी पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुएकहा, ''जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है.. युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया है... उनमें से एक को भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो।

क्या चुनावी गीत 'जय भवानी' से उद्धव ठाकरे को मिल पाएगी सियासी धार?

ऐसे मिला पुरानी पिच पर खेलने का मौका

महाराष्ट्र की सियासत तब गर्म होने लगी, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी में चुनावी गीत लॉन्च किया। जब चुनाव आयोग ने इस पर नोटिस दिया, तो उद्धव ठाकरे ने इसको महाराष्ट्र की अस्मिता और अपनी पार्टी की पुरानी हिंदुत्ववादी छवि से जोड़ना शुरू कर दिया।

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के चुनावी गीत के बाद अचानक सियासत गरमा गई है। इस सियासत के गर्म होने की वजह चुनावी गीत में 'जय भवानी' और 'हिंदू' शब्द का आना है। दरअसल, चुनाव आयोग ने इस गीत के बाद इन शब्दों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नोटिस देखकर इनको हटाने के लिए कहा था। हालांकि उद्धव ठाकरे ने शब्दों को हटाने की बात तो दूर, बल्कि इन्हीं शब्दों को अब महाराष्ट्र की सियासत में अपना बड़ा सियासी हथियार बना कर नया दांव चल दिया है। सियासी जानकारों के मुताबिक उद्धव की सेना इन शब्दों के साथ कमजोर पड़ रही अपनी हिंदुत्ववादी छवि को निखारने में लग गई है। इस संबंध में मंगलवार को यूबीटी के नेताओं की एक बैठक भी हुई। फिलहाल समूचे महाराष्ट्र में एक संदेश के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसे आगे बढ़ाने लगी है। दरअसल, महाराष्ट्र की सियासत तब गर्म होने लगी, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी में चुनावी गीत लॉन्च किया। जब चुनाव आयोग ने इस पर नोटिस दिया, तो उद्धव ठाकरे ने इसको महाराष्ट्र की अस्मिता और अपनी पार्टी की पुरानी हिंदुत्ववादी छवि से जोड़ना शुरू कर दिया। शिवसेना सेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस नोटिस को मिलने के बाद कहा कि वह अपनी पार्टी के गीत से न तो 'जय भवानी' हटाने जा रहे हैं और न ही उसके किसी शब्द को कम करने वाले हैं। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना की जो परंपराएं चलती चली आ रही है, उसे किसी कीमत पर ना तो कमजोर होने दिया जाएगा और ना ही किसी तंत्र के सामने झुकने दिया जाएगा। इन्हीं परंपराओं में 'जय भवानी-जय शिवाजी' का उदघोष भी शामिल है। इस मामले में पार्टी के बड़े नेताओं ने मंगलवार को बैठक कर उद्घोष को हमेशा की तरह आगे बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए गए।

महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नोटिस तो दे दिया, लेकिन पार्टी ने इससे कमजोर पड़ रही अपनी हिंदुत्ववादी छवि को चमकाने की व्यवस्था कर ली। सियासी जानकार और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शितोले कहते हैं कि दरअसल शिवसेना जब से इंडिया गठबंधन के साथ आई है, तब से उसके हिंदुत्व की छवि को कमजोर कहा जाने लगा है। अब जब चुनाव आयोग ने उनके एक चुनावी गीत के जय भवानी और हिंदू जैसे शब्दों पर आपत्ति की, तो उद्धव ठाकरे ने इसको बड़ा मौका समझ कर लपक लिया। वह कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करके चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस को जवाब देने की बजाय, यह संदेश दिया कि जय भवानी और हिंदू जैसे शब्द बिल्कुल नहीं हटने वाले।

सियासी जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना शुरुआत से ही हिंदुत्ववादी विचारधारा की पार्टी के तौर पर पहचानी जाती है। लेकिन हाल के दिनों में हुई सियासी उथल-पुथल के बीच जब कांग्रेस और अन्य दलों के साथ गठबंधन हुआ, तो उसकी इस विचारधारा को लेकर तमाम तरह के सवालिया निशान उठने लगे। राजनीतिक विश्लेषक हेमंत लीलाधर साठे कहते हैं कि इस विवाद के शुरू होने के साथ ही जिस तरह उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, देवी तुलजा भवानी और हिंदवी स्वराज की बात कही है। उससे इस बात का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना किस तरह इस मामले को अपनी हिंदुत्ववादी छवि के साथ आगे लेकर जा रही है। वह कहते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक तरह से सियासी ऑक्सीजन के तौर पर देख रही है। महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ आने पर यह पहला मौका है, जब जय भवानी और हिंदू शब्द के साथ खुलकर उद्धव ठाकरे की सेना ने मोर्चा संभाला है।

चुनाव आयोग की ओर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नोटिस भेजा गया, तो उनकी पार्टी भी अपने उन सभी पुराने मामलों को लेकर सामने आ रही है, जिसमें उसकी हिंदुत्ववादी छवि चमकती थी। नोटिस मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने याद दिलाया कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से इसलिए रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के लिए बड़ा अभियान चलाया था। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी हमला करते हुए कहा कि अगर हमारे गीत में 'जय भवानी' और 'हिंदू' नजर आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैलियों में बोले गए ऐसे शब्दों पर चुनाव आयोग क्यों नोटिस नहीं देता है।

लू से बचने के लिए ये 5 जड़ी-बूटियां शरीर को देंगी ठंडक

भीषण गर्मी से बचने के लिए न जाने हम सभी कितना उपाय करते हैं लेकिन फिर भी लू लग जाती है। लू से बचने के लिए इन 5 जड़ी-बूटियों का करें सेवन, मिलेंगी शरीर को ठंडक। यहां पांच ताज़ा जड़ी-बूटियां दी गई हैं। जिनके सेवन से आप खुद को कूल महसूस करेंगे, आइए आपको बताते हैं।

गर्मियों का मौसम शुरु हो चुका है। इस मौसम खतरनाक लू चलती है जिससे इंसान की सेहत खराब होने लगती है। गर्मियों में खुद को हेल्दी रखने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजें हम सभी खाते हैं। हालांकि, आप इन जड़ी-बूटियों के सेवन से गर्मी में कूल नजर आएंगे। चिलचिलाती गर्मी आपके हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने के लिए इन हर्ब्स का सेवन जरुर करें। यहां पांच ताज़ा जड़ी-बूटियां दी गई हैं। जिनके सेवन से आप खुद को कूल महसूस करेंगे, आइए आपको बताते हैं।

धनिया

धनिया में कूलिंग के गुण होते हैं जो गर्मी झेलने में सुधार करने में मदद करते हैं। यह एंटीऑक्सिडेंट से भी भरपूर है जो मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। धनिए इस्तेमाल चटनी से लेकर हर सब्जी में करते हैं। हर धनिए के अधिक सेवन से गर्मी का एहसास कम होता।

पुदीना

गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग पुदीना का इस्तेमाल करते हैं। पुदीना में शीतलन प्रभाव होता है, जो शरीर के तापमान को कम करने और थर्मोरेग्यूलेशन में सहायता करता है। पुदीने का पानी पीना या फिर आप चटनी बनाकर खा सकते हैं। वास्तव, पुदीना एक ठंडी जड़ी-बूटी है। गर्मियों में इसका सेवन करने से शरीर को ठंड़क मिलती है। पुदीने का पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है।

सौंफ

सौंफ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट और आवश्यक तेल होते हैं, जो पेट फूलना और पाचन से राहत दिलाने में मदद करते हैं। सौंफ का इस्तेमाल पारंपारिक रुप से शरीर को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठंडाई में भी सौंफ का प्रयोग होता है। आप सौंफ का पानी पी सकते हैं इससे गर्मी भी कम होगी और पाचन भी दुरुस्त रहेगा। वहीं आप सौंफ को प्रयोग खाना बनाते समय सब्जियों में कर सकते हैं।

इलायची

इलायची में शीतलन यौगिक होते हैं जो शरीर की गर्मी को कम करने और पाचन में सहायता करते हैं। इलायची का प्रयोग सबसे ज्यादा मसालों में प्रयोग होता है। यह भोजन में स्वाद के साथ सुगंध को बढ़ाती है। इलायची खाने से शरीर की गर्मी कम होती है,जो आपको ठंडक और एनर्जेटिक महसूस होता है।

गुड़हल या हिबिस्कस

हिबिकस अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से निपटने में मदद करता है और शरीर को प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। आप गुड़हल की चाय बनाकर पी सकते हैं जो शरीर को ठंडक पहुंचाती है। इसके साथ ही ये कब्ज की समस्या भी दूर करती है। गर्मी में कूल रहने के लिए आप हिबिस्कस टी जरुर पिएं।

भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से भाग्य का मिलता है साथ...

जानिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

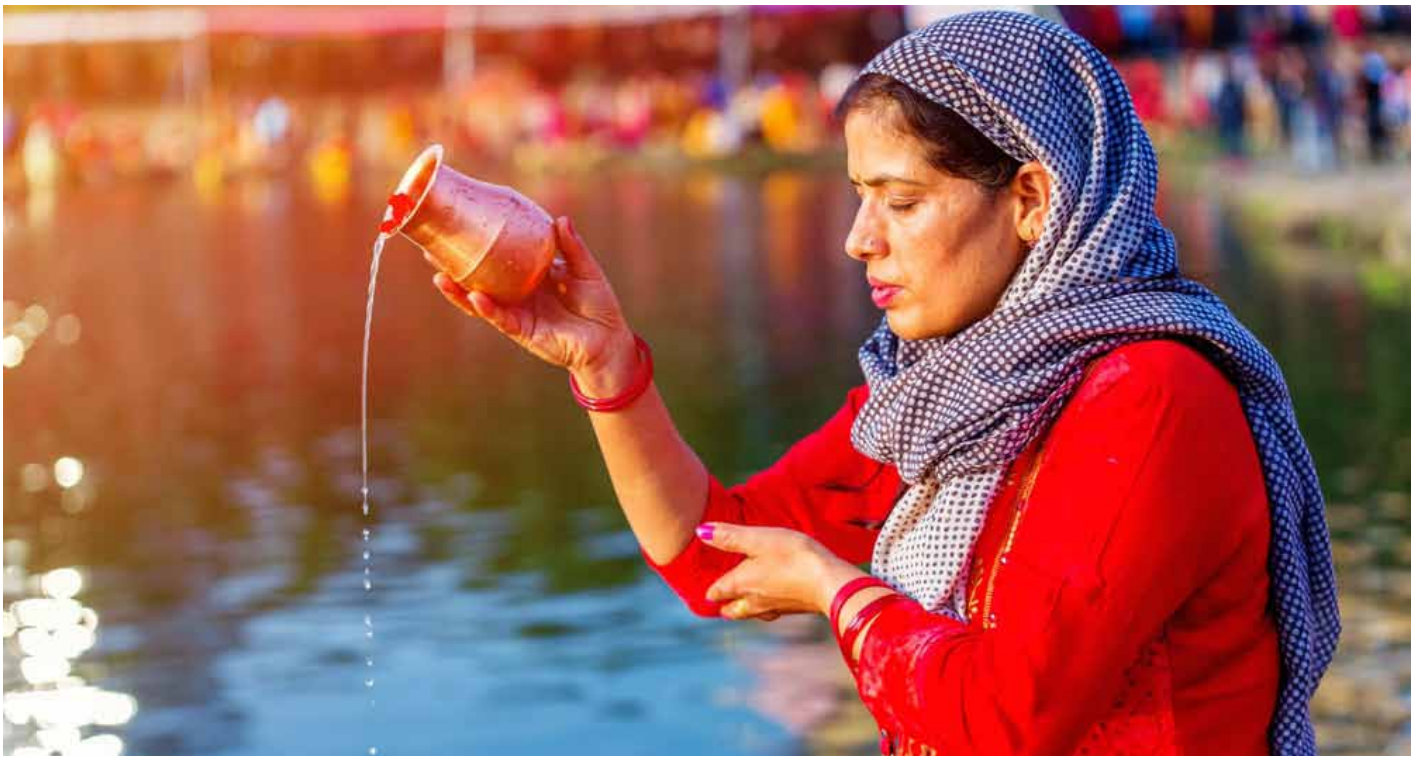

हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्थान प्राप्त है। सूर्य के बिना धरती पर अंधकार छा जाता है। वहीं सूर्यदेव को जल अर्पित करने के अनगिनत फायदे होते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक लाभ प्राप्त होता है और आर्थिक उन्नति मिलती है। सूर्य अच्छी सेहत और जीवन शक्ति का भंडार है। बताया जाता है कि आप सूर्य के प्रभाव में जितना अधिक रहेंगे आप उतना ही अधिक सेहतमंद रहेंगे।

हांलाकि आजकल लोग सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए चारों तरफ से खिड़कियां-दरवाजे बंद रखते हैं। इसी वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी होती है और अन्य कई रोग हमें घेर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश का और सूर्य को जल अर्पित करने का अपना धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है।

वैज्ञानिक महत्व और लाभ

विज्ञान के मुताबिक सूर्य को जल अर्पित करने के दौरान जब हम पानी की धाराओं में से सूर्य की तरफ देखते हैं। तो उससे निकलने वाली 7 तरह की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं। इन किरणों से आंखों को लाभ मिलता है और आंख की रोशनी अच्छी होती है। साथ ही आंखों का रंग भी नेचुरल बना रहता है। बता दें कि जो लोग रोजाना सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उनको आंख संबंधी रोग नहीं होते हैं। वहीं सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है।

धार्मिक महत्त्व और लाभ

अथर्ववेद के एक मंत्र के अनुसार, सूर्य औषधि बनाने में सहायक है। सूर्य विश्व में प्राण स्वरूप विद्यमान है और यह अपनी किरणों से जीवों के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। रविवार का दिन सूर्य को समर्पित होता है और भगवान सूर्य सप्तमी तिथि के देवता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय 'ऊं घृणि सूर्याय नमः' या 'ऊँ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए। बता दें कि सूर्य को भाग्य का कारक माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है। उनके सरकारी कार्यों में रुकावट आती है और व्यापार नहीं सही चलता है। कार्यस्थल पर हमेशा उच्च पदाधिकारियों से अनबन होती रहती है।

सूर्य को ऐसे करें मजबूत

आपको बता दें कि रोजाना सूर्य को जल अर्पित कर आप कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। इससे सूर्य देव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संकटों को हर लेते हैं। साथ ही धन-धान्य, पुत्र, मित्र, आरोग्य, यश, तेज, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य प्रदान करते हैं। सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रोजाना जल अर्पित करने के साथ ही हर रविवार या फिर किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के रविवार को नदी या बहते जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करने चाहिए।

गर्मी में स्किन पर लगाएं रोजमेरी और मिंट का फेस पैक, दमकने त्वचा...

गर्मी के मौसम में अपनी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देने व उसे ग्लोइंग बनाने के लिए फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप रोजमेरी और मिंट की मदद से फेस पैक बनाते हैं तो इससे आपकी स्किन को बहुत अधिक फायदा मिलता है।

गर्मी का मौसम शुरू होते ही स्किन की परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। अमूमन इस मौसम में पसीना, ऑयल से लेकर एक्ने, और स्किन में जलन जैसी कई तरह की परेशानियां होती हैं। यह देखने में आता है कि समर में स्किन की केयर करने के लिए लोग तरह-तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। जबकि आप नेचुरल तरीके से भी अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। मसलन, इस मौसम में अपनी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देने व उसे ग्लोइंग बनाने के लिए फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप रोजमेरी और मिंट की मदद से फेस पैक बनाते हैं तो इससे आपकी स्किन को बहुत अधिक फायदा मिलता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको गर्मी के मौसम के लिए रोजमेरी और मिंट की मदद से बनने वाले कुछ फेस पैक के बारे में बता रहे हैं-

गर्मी में स्किन को डीप क्लीन करने के लिए आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आवश्यक सामग्री

- 1 बड़ा चम्मच सूखी रोजमेरी
- 1 बड़ा चम्मच सूखे पुदीने की पत्तियां (बारीक पाउडर में कुचली हुई)
- 1 बड़ा चम्मच ओटमील
- आवश्यकतानुसार गुलाब जल

फेस पैक बनाने का तरीका

- सबसे पहले एक बाउल में क्रश की हुई सूखी रोजमेरी, पुदीने की पत्तियां और ओटमील मिक्स करें।
- अब इसमें थोड़ा गुलाब जल मिलाएं, ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाएं।
- अब तैयार पैक को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और सर्कुलर मोशन में धीरे-धीरे मालिश करें।
- इसे 15-20 मिनट तक लगा रहने दें।
- अंत में, गुनगुने पानी से धो लें और थपथपा कर सुखा लें।

रोज़मेरी-मिंट हाइड्रेटिंग फेस पैक

गर्मी में लगातार पसीना आने के कारण स्किन को अतिरिक्त हाइड्रेशन की जरूरत होती है। ऐसे में यह फेस पैक इस्तेमाल किया जा सकता है।

आवश्यक सामग्री

- 2 बड़े चम्मच रोजमेरी
- 2 बड़े चम्मच पुदीने की पत्तियां
- 1 बड़ा चम्मच शहद
- 1 बड़ा चम्मच सादा दही

इस्तेमाल का तरीका

- सबसे पहले रोजमेरी और पुदीने की पत्तियों को एक साथ पीसकर बारीक पेस्ट बना लें।
- अब इस पेस्ट में शहद और दही डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- तैयार मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं।
- इसे 15-20 मिनट तक लगा रहने दें।
- अंत में, इसे गुनगुने पानी से धो लें और थपथपा कर सुखा लें।

18 जून को पावो नूरमी खेलों में भाग लेंगे नीरज चोपड़ा

मैक्स डेह्रिंग से मिल सकती है कड़ी चुनौती

चोपड़ा 10 मई को दोहा डायमंड लीग मीट से अपने सत्र की शुरुआत करेंगे। पावो नूरमी खेलों का नाम फिनलैंड के मध्य और लंबी दूरी के धावक के नाम पर रखा गया है। यह विश्व एथलेटिक्स की 'कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड सीरीज' स्तर की प्रतियोगिता है। यह डायमंड लीग मीट सीरीज के बाहर सबसे प्रतिष्ठित एक दिवसीय प्रतियोगिताओं में से एक है।

दिग्गज भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 18 जून को फिनलैंड के तुर्कू में होने जा रहे पावो नूरमी खेलों में खेलते नजर आएंगे। इसमें उन्हें जर्मनी के 19 वर्षीय मैक्स डेह्रिंग से कड़ी चुनौती मिल सकती है। इसकी जानकारी पावो नूरमी खेलों के आयोजकों ने दी। 2022 सत्र में 89.30 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता था। यह उनके करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो है। उन्होंने 2023 में चोटिल होने के कारण इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। चोपड़ा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 89.94 मीटर है। वहीं, डेह्रिंग हाल ही में 90 मीटर की बाधा पार करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने।

डायमंड लीग मीट से सत्र की शुरुआत करेंगे चोपड़ा : चोपड़ा 10 मई को दोहा डायमंड लीग मीट से अपने सत्र की शुरुआत करेंगे। पावो नूरमी खेलों का नाम फिनलैंड के मध्य और लंबी दूरी के धावक के नाम पर रखा गया है। यह विश्व एथलेटिक्स की 'कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड सीरीज' स्तर की प्रतियोगिता है। यह डायमंड लीग मीट सीरीज के बाहर सबसे प्रतिष्ठित एक दिवसीय प्रतियोगिताओं में से एक है। टूर्नामेंट के आधिकारिक वेबसाइट पर खिलाड़ियों से करार के लिए जिम्मेदार आर्टटू सलोनेन ने कहा, 'भाला फेंक ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा जून में तुर्कू लौटेंगे। चोपड़ा एक साल के ब्रेक के बाद पावो नूरमी खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे जहां उनका सामना बेहतरीन प्रतियोगियों के समूह से होगा। प्रतियोगिता 18 जून को तुर्कू में होगी।'

जूलियन वेबर और मैक्स डेह्रिंग से भी किया गया अनुबंध

उन्होंने बताया कि चोपड़ा के अलावा जर्मनी के दिग्गज जूलियन वेबर और मैक्स डेह्रिंग के साथ भी अनुबंध किया गया है। उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य पेरिस ओलंपिक से पहले तुर्कू में गर्मियों की सबसे कठिन भाला फेंक प्रतियोगिता को आयोजित करना है। इसके लिए दूसरे खिलाड़ियों के साथ बातचीत जारी है। हम चाहते हैं कि शीर्ष घरेलू नाम तुर्कू में प्रतिस्पर्धा करें जिसका नेतृत्व ओलिवर हेलैंडर (जिन्होंने 2022 सत्र में 89.83 मीटर की दूरी के साथ स्वर्ण पदक जीता था) करेंगे।'

अनुपमा उपाध्याय ने कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता

बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और थारुन मन्नेपल्ली ने उरालस्क में कजाखस्तान अंतरराष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब अपने नाम किये। अल्मोड़ा की 19 साल की अनुपमा ने पिछले महीने पोलिश अंतरराष्ट्रीय चैलेंज में जीत हासिल की थी। उन्होंने फाइनल में 41 मिनट में हमवतन इशारानी बरुआ पर 21-15 21-16 से जीत दर्ज कर लगातार दूसरा खिताब हासिल किया।

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और थारुन मन्नेपल्ली ने शनिवार को उरालस्क में कजाखस्तान अंतरराष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब अपने नाम किये। अल्मोड़ा की 19 साल की अनुपमा ने पिछले महीने पोलिश अंतरराष्ट्रीय चैलेंज में जीत हासिल की थी। उन्होंने फाइनल में 41 मिनट में हमवतन इशारानी बरुआ पर 21-15 21-16 से जीत दर्ज कर लगातार दूसरा खिताब हासिल किया। वहीं पिछले साल दिसंबर में गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में उपविजेता रहे 22 वर्षीय थारुन ने आठवें वरीय मलेशिया के सूंग जू वेन को 21-10, 21-19 से हराकर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता। मिश्रित युगल के फाइनल में भारत के संजय श्रीवत्स धनराज और मनीषा के की जोड़ी को मलेशिया के वोंग टीएन सी और लिम चिव सिएन की जोड़ी से 21-9, 7-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। पूर्व सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियन अनुपमा इस हफ्ते अच्छी फॉर्म में दिखीं, उन्होंने फाइनल में पहुंचने से पहले हमवतन हर्षिता राउत, चेक गणराज्य की टेरेजा स्वाबिकोवा, हमवतन देविका सिहाग और जापान की सोरानो योशिकावा को मात दी। अनुपमा ने 2021 में इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज, पोलिश ओपन (2022 और 2024) और 2023 में ताजिकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज जीती है। थारुन ने फाइनल से पहले हमवतन गगन बाल्यान, 2022 विश्व जूनियर चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता एस शंकर मुथुसैमी, कजाकिस्तान के दिमित्री पनारिन और वियतनाम के ले डुक फाट को पराजित किया।

अयोध्या के अलावा भारत के इन शहरों में भी हैं प्रसिद्ध राम मंदिर

भारत में कई फेमस और प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से एक सबसे ज्यादा फेमस मंदिर आयोध्या का श्रीराम मंदिर है। आज हम आपको भारत में स्थित उन राम मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भारत में कई फेमस और प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से एक सबसे ज्यादा फेमस मंदिर आयोध्या का श्रीराम मंदिर है। बीते 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण-प्रतिष्ठा की धूम न सिर्फ पूरे भारत बल्कि विश्व में गूंजी थी। अयोध्या का राम मंदिर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में फेमस है। आपको बता दें कि श्रीराम की नगरी अयोध्या के अलावा भारत के अन्य शहरों में फेमस राम मंदिर स्थित है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको भारत में स्थित उन राम मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में आपको भी इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करना चाहिए।

राम राजा मंदिर

उत्तर भारत में अयोध्या के अलावा जब भी किसी अन्य फेमस और पवित्र मंदिर का जिक्र किया जाता है, तो राम राजा मंदिर का जिक्र जरूर होता है। मध्य प्रदेश के ओरछा में यह मंदिर मौजूद है। बता दें कि इस मंदिर में श्रीराम को राजा स्वरूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में राजा राम को हर दिन शस्त्र सलामी दी जाती है। राम राजा मंदिर में श्रीराम के अलावा माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भगवान नरसिंह और महाराजा सुग्रीव की मूर्तियां स्थापित हैं।

त्रिप्रायर श्री राम मंदिर

केरल अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। केरल का त्रिप्रायर श्री राम मंदिर काफी फेमस है। त्रिप्रायर श्री राम मंदिर पूरे दक्षिण-भारत का गौरव माना जाता है। हर दिन हजारों की संख्या में भक्त अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित त्रिप्रायर मंदिर में श्रीराम की त्रिप्रयारप्पन या त्रिप्रायार थेवर पूजा की जाती है। मान्यता के मुताबिक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा-अर्चना भगवान श्रीकृष्ण करते थे। भगवान श्रीकृष्ण को भी श्रीहरि विष्णु का अवतार माना जाता है।

रामास्वामी मंदिर

रामास्वामी मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह मंदिर भी भगवान श्रीराम को समर्पित है। रामायण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। रामास्वामी मंदिर की दीवारों पर मौजूद वास्तुकला रामायण काल के सभी फेमस घटनाओं को दर्शाता है। दक्षिण भारतीय लोग इस मंदिर को देश का अयोध्या मानते हैं। मंदिर में प्रभु राम, मां सीता और लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न की मूर्ति स्थापित है।

सीता रामचंद्रस्वामी मंदिर

यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। तेलंगाना में गोदावरी नदी के तट पर यह पवित्र मंदिर स्थित है। राम नवमी के मौके पर इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सीता रामचंद्रस्वामी मंदिर के पौराणिक कथा के मुताबिक यह मंदिर उस जगह स्थापित है, जहां पर जब प्रभु राम ने माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए गोदावरी नदी पार की थी। सीता रामचंद्रस्वामी मंदिर में श्रीराम और मां सीता की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

कालाराम मंदिर

आपको बता दें कि कालाराम मंदिर देश के सबसे अहम मंदिरों में से एक है। महाराष्ट्र राज्य के शहर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में यह पवित्र और फेमस मंदिर स्थित है। यहां पर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह भारत का एक मात्र ऐसा मंदिर है, जहां भगवान श्रीराम की काले रंग की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर को कालाराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार, गोदावरी नदी में भगवान राम के काले रंग की मूर्ति मिली थी। भगवान राम के अलावा मंदिर में मां सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित हैं।

शनि देव की कृपा पाने के लिए इन मंत्रों का करें जाप, कष्टों का होगा निवारण

नवग्रहों में सभी ग्रहों का अपना अलग स्थान है। इनमें से शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में उन्हें न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि दोष होता है, तो वह जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करता है। साथ ही व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होने लगता है। वहीं अगर जातक पर शनि देव की कृपा बनी हो, तो उसकी तरक्की के योग बनने लगते हैं। मान्यता है कि विधिनुसार शनि देव की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सभी रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। इसलिए उनकी पूजा का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा को विधिनुसार सम्पन्न करने के लिए कुछ मंत्रों का जाप शुभ होता है। ऐसे में आइए इन मंत्रों के बारे में जान लेते हैं।

शनिदेव के प्रमुख मंत्र

शनि गायत्री मंत्र

ॐ शनैश्चराय विदमहे छायापुत्राय धीमहि ।

शनि बीज मंत्र

ॐ प्रां प्रीं प्रों सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि स्तोत्र

ॐ नीलांजन समाभासं रवि पुत्रं यमाग्रजम ।

छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम ।।

शनि पीड़ाहर स्तोत्र

सुर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः ।

दीर्घचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः ।।

तन्नो मंदः प्रचोदयात ।।

शनिदेव को प्रसन्न करने वाले सरल मंत्र

'ॐ शं शनैश्चराय नमः'

'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः'

'ॐ शन्नो देविर्भिष्टयः आपो भवन्तु पीतये।

सय्योंरभीस्त्रवन्तुनः।।

शनि का पौराणिक मंत्र

ऊँ ह्रिं नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम।

छाया मार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।।

सामान्य मंत्र : ॐ शं शनैश्चराय नमः।

शनि का वैदिक मंत्र

ऊँ शन्नोदेवीर- भिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये शंय्योरभिस्त्रवन्तुनः।

श्री शनि चालीसा

जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल।
दीनन के दुख दूर करि, कीजै नाथ निहाल॥
जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज।
करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज॥
जयति जयति शनिदेव दयाला।
करत सदा भक्तन प्रतिपाला॥
चारि भुजा, तनु श्याम विराजै।
माथे रतन मुकुट छबि छाजै॥
परम विशाल मनोहर भाला।
टेढ़ी दृष्टि भृकुटि विकराला॥
कुण्डल श्रवण चमाचम चमके।
हिय माल मुक्तन मणि दमके॥
कर में गदा त्रिशूल कुठारा।
पल बिच करैं अरिहिं संहारा॥
पिंगल, कृष्णो, छाया नन्दन।
यम, कोणस्थ, रौद्र, दुखभंजन॥
सौरी, मन्द, शनी, दश नामा।
भानु पुत्र पूजहिं सब कामा॥
जा पर प्रभु प्रसन्न ह्वैं जाहीं।
रंकहुँ राव करैं क्षण माहीं॥
पर्वतहू तृण होई निहारत।
तृणहू को पर्वत करि डारत॥
राज मिलत बन रामहिं दीन्हयो।
कैकेइहुँ की मति हरि लीन्हयो॥
बनहूँ में मृग कपट दिखाई।
मातु जानकी गई चुराई॥
लखनहिं शक्ति विकल करिडारा।
मचिगा दल में हाहाकारा॥
रावण की गति-मति बौराई।
रामचंद्र सों बैर बढ़ाई॥
दियो कीट करि कंचन लंका।
बजि बजरंग बीर की डंका॥
नृप विक्रम पर तुहि पगु धारा।
चित्र मयूर निगलि गै हारा॥
हार नौलखा लाग्यो चोरी।
हाथ पैर डरवायो तोरी॥
भारी दशा निकृष्ट दिखायो।
तेलिहिं घर कोल्हू चलवायो॥
विनय राग दीपक महं कीन्हयों।
तब प्रसन्न प्रभु ह्वै सुख दीन्हयों॥
हरिश्चन्द्र नृप नारि बिकानी।
आपहुं भरे डोम घर पानी॥
तैसे नल पर दशा सिरानी।
भूंजी-मीन कूद गई पानी॥
श्री शंकरहिं गह्यो जब जाई।
पारवती को सती कराई॥
तनिक विलोकत ही करि रीसा।
नभ उड़ि गयो गौरिसुत सीसा॥
पांडव पर भै दशा तुम्हारी।
बची द्रौपदी होति उघारी॥
कौरव के भी गति मति मारयो।
युद्ध महाभारत करि डारयो॥
रवि कहं मुख महं धरि तत्काला।
लेकर कूदि परयो पाताला॥
शेष देव-लखि विनती लाई।
रवि को मुख ते दियो छुड़ाई॥
वाहन प्रभु के सात सुजाना।
जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना॥
जंबुक सिंह आदि नख धारी।
सो फल ज्योतिष कहत पुकारी॥
गज वाहन लक्ष्मी गृह आवैं।
हय ते सुख सम्पति उपजावैं॥
गर्दभ हानि करै बहु काजा।
सिंह सिद्धकर राज समाजा॥
जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारै।
मृग दे कष्ट प्राण संहारै॥
जब आवहिं प्रभु स्वान सवारी।
चोरी आदि होय डर भारी॥
तैसहि चारि चरण यह नामा।
स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा॥
लौह चरण पर जब प्रभु आवैं।
धन जन सम्पत्ति नष्ट करावैं॥
समता ताम्र रजत शुभकारी।
स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी॥
जो यह शनि चरित्र नित गावै।
कबहुं न दशा निकृष्ट सतावै॥
अद्भुत नाथ दिखावैं लीला।
करैं शत्रु के नशि बलि ढीला॥
जो पंडित सुयोग्य बुलवाई।
विधिवत शनि ग्रह शांति कराई॥
पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत।
दीप दान दै बहु सुख पावत॥
कहत राम सुन्दर प्रभु दासा।
शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा॥

दोहा

पाठ शनिश्चर देव को, की हों 'भक्त' तैयार।
करत पाठ चालीस दिन, हो भवसागर पार॥

अक्षय तृतीया पर्व

हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष...

अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओ के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं।

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है, जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाले दान-पुण्य, पूजा-पाठ, जाप-तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है, ऐसे में आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सबकुछ।

इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार, 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4 बजकर 17 मिनट पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 02 बजकर 50 मिनट पर होगी। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 48 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 23 मिनट तक रहेगा।

शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है। यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने-चांदी के आभूषण. घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से सम्बंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरम्भ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान-पुण्य,पूजा-पाठ अक्षय रहता है अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता।

अक्षय तृतीया का महत्व : अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है।

अक्षय तृतीया का ज्योतिषीय महत्व : हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भी इस तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं, साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज्यादा चमकीले यानी सबसे ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना जाता है। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष तिथि माना गया है। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख- समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है।| अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करके श्री विष्णुजी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप-अगरबत्ती और चन्दन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेंहू, या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान-दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।

अक्षय तृतीया पर्व से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य

1. अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है इस कारण से इस चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है।
2. अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ था।
3. भगवान विष्णु के अवतार नर-नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था।
4. ब्रह्माजी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था।
5. अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्रीगणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया गया था।
6. अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ।
7. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही मां गंगा का पृथ्वी में आगमन हुआ था।
8. इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं ।
9. अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृन्दावन के श्री बांकेबिहारी जी के मंदिर में सम्पूर्ण वर्ष में केवल एक बार श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं।
10. अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्धि पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है।

बाराही देवी मंदिर में दर्शन मात्र से दूर होती है गंभीर बीमारियां

देश के 51 शक्तिपीठों में एक बाराही देवी शक्तिपीठ है। इसको उत्तरभवानी देवी का मंदिर भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इस स्थान पर माता सती का जबड़ा गिरा था। इस मंदिर में जो भी जातक दर्शन करता है, उसके आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक बाराही देवी मंदिर विश्व फेमस है। मान्यता के मुताबिक इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं। यहां तक की नेत्रहीन व्यक्ति के आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। शिव पुराण के मुताबिक माता सती ने भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया था।

जिसके बाद भगवान शिव इस घटना से इतना अधिक विचलित हुए कि वह माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह देख भगवान श्रीहरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। माता सती के शरीर के टुकड़े जहां-जहां गिरे वह शक्तिपीठ बन गए।

इन्हीं शक्तिपीठों में बाराही देवी शक्तिपीठ है। इसको उत्तरभवानी देवी का मंदिर भी कहा जाता है। बता दें कि देश भर में फेमस 51 शक्तिपीठों में बाराही देवी मंदिर 354वें स्थान पर है। बताया जाता है कि इस स्थान पर माता सती का जबड़ा गिरा था। इस मंदिर में जो भी जातक दर्शन करता है, उसके आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है।

बाराही देवी मंदिर : अयोध्या से करीब 36 किलोमीटर दूर बाराही देवी मंदिर स्थित है। बाराही देवी मंदिर वटवृक्ष की जड़ों से घिरा हुआ है। लगभग एक किलोमीटर में वटवृक्ष का पेड़ फैला हुआ है। यह वृक्ष एशिया के दूसरे सबसे बड़े वटवृक्षों में से एक है। बताया जा रहा है कि यह पेड़ करीब 1800 साल पुराना है।

भक्तों में अटूट श्रद्धा देखने को मिलती है

बाराही देवी मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर को लेकर भक्तों में अटूट श्रद्धा देखने को मिलती है। मान्यता के अनुसार, इस मंदिर में माता के दर्शन से कई बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। पुजारी ने बताया कि मंदिर में एक नेत्रहीन व्यक्ति आया था, जो कई अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा चुके थे, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिला था। इसके बाद वह निराश होकर मंदिर दर्शन के लिए आया। मंदिर में आने के बाद नेत्रहीन व्यक्ति की आंखों में वटवृक्ष से निकलने वाला दूध डाला गया था। जिसके बाद माता रानी के चमत्कार से नेत्रहीन व्यक्ति की आंखें बिलकुल ठीक हो गईं। बताया जाता है कि नवरात्रि अष्टमी को मेला लगता है। इस दौरान दूर-दूर से लोग मां बाराही के दर्शन करने नंगे पैर आते हैं। मंदिर में आने वाले भक्त सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी हैं।

इस तरह से भोग लगाने पर नाराज हो सकते हैं इष्टदेव

भगवान को भोग लगाने व बनाने के दौरान कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग भोग लगाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उनके इष्टदेव उनसे नाराज हो सकते हैं।

सनातन धर्म में पूजा-पाठ में सही नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है। भक्त अपने आराध्य की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं औऱ उनको भोग लगाते हैं। मान्यता के मुताबिक भगवान को भोग स्वरूप जो प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसको भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। लेकिन भोग लगाने व बनाने के दौरान कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग भोग लगाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उनके इष्टदेव उनसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए कुछ बातों का खास ख्याल ऱखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि भगवान को भोग लगाने के बाद उसे सबसे पहले किसे खिलाना चाहिए।

न करें ये गलती : पूजा के दौरान लोगों को भूलकर भी कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। कई लोग भगवान के लिए जो भोग बनाकर तैयार करते हैं, उसी में थोड़ा सा अलग निकालकर खाना शुरूकर देते हैं। फिर उसमें से निकालकर भगवान को भोग लगा देते हैं। लेकिन बता दें कि शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। इसलिए अगर आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो उसका सीधे भोग लगाना चाहिए।

भगवान को भोग लगाने के बाद इसे सबसे पहले गाय को खिलाना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक गौ माता में सभी देवी-देवता वास करते हैं और गाय को भोग खिलाने से सभी देवी-देवता प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर आपको भोग खिलाने के लिए गौ माता नहीं मिल रही हैं, तो आप इसको घर के सबसे छोटे बच्चे को खिला सकते हैं। बताया जाता है कि छोटे बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए भोग आप बच्चे को खिला सकती हैं। इससे आपको शुभ परिणाम मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भोग लगाने के दौरान कई बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। भगवान को प्याज और लहसुन वाला भोग नहीं लगाना चाहिए। भोग बनाने वाले स्थान को साफ-सुथरा रखना चाहिए। साथ ही इस स्थान को गंगाजल से पवित्र करना चाहिए।

आंखों की नमी बनाए रखने-रोशनी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपाय...

वैश्विक स्तर पर आंखों से संबंधित कई प्रकार की बीमारियों को समय के साथ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। कुछ दशकों पहले तक आंखों की समस्याओं को उम्र बढ़ने के साथ होने वाले विकारों के रूप में जाना जाता था, हालांकि अब कम उम्र के लोग भी इसके शिकार पाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स बताते हैं, लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के अलावा बढ़ा हुआ स्क्रीनटाइम भी आंखों के लिए नुकसानदायक है। इसके कारण कम दिखाई देने से लेकर, ड्राई आइज, आंखों में दर्द, ग्लूकोमा और कुछ स्थितियों में रोशनी तक चले जाने की समस्या भी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार के सेवन के साथ नियमित रूप से कुछ अभ्यास करना लाभकारी हो सकता है। पलकों को झपकाने की आदत इसमें सबसे फायदेमंद मानी जाती रही है। माना जाता है कि पलकों को झपकाने से आंखों की नमी बनी रहती है और ड्राई आइज की समस्या का जोखिम कम होता है। हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस आदत को आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला भी पाया है। क्या आप समय-समय पर पलकों को झपकाते हैं?

पलकें झपकाने से आराम

अमेरिका की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में हुए अध्ययन के मुताबिक, बार-बार पलक झपकने से न सिर्फ आंखों की नमी को बनाए रखने में मदद मिलती है साथ ही इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि जब आप पलक झपकाते है तो इससे रेटिना उत्तेजित होती है जिससे छवि साफ दिखने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं पलकें झपकने से हमारा दिमाग भी सक्रिय मोड में रहता है। हम जितने देर जागते हैं, उतनी देर में पलकें

झपकने से हमारी आंखें करीब 10% समय बंद रहती है, इससे दिमाग को आराम मिलता है।

अध्ययन में क्या पता चला?

विश्वविद्यालय में न्यूरोसाइंटिस्ट बिन यांग ने अपने प्रकाशित पेपर में लिखा है, हमने पाया है कि पलक झपकने से रेटिना की उत्तेजना की शक्ति बढ़ जाती है। आंखों की मांसपेशियों के लिए ये सरल व्यायाम भी है। मांसपेशियां जितनी सक्रिय रहेंगी, रक्त का संचार भी उतना ही ठीक रहता है जिससे आप न सिर्फ आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं साथ ही इससे संबंधित कई प्रकार के विकारों को भी कम किया जा सकता है। पिछले शोधों से पता चलता है कि पलकें झपकाने से हमारी ध्यान क्षमता भी एक्टिव होती है, वस्तुओं को पहचानने में मदद मिलती है। इसके अलावा इससे आंखों को सूखने से बचाने में मदद मिलती है जो कई प्रकार की बीमारियों का प्रमुख कारण रहा है।

ड्राई आइज की समस्या

अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि पलकों को झपकने से आंखें, मस्तिष्क से मिल रही दृश्य संबंधी जानकारी को पुनः स्वरूपित कर पाती हैं। जिन लोगों में कुछ कारणों से पलकों के न झपकने की समस्या होती है उनमें ड्राई आइज जैसे विकारों का खतरा भी अधिक हो सकता है। ड्राई आइज को अंधेपन का एक प्रमुख जोखिम कारक माना जाता रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पलकें झपकाने के कई लाभ हैं पर अनावश्यक रूप से पलकों को झपकाने से नुकसान भी हो सकता है।

ज्यादा पलकें झपकाने के भी नुकसान

शोधकर्ताओं ने कहा, आंखों की नमी बरकरार रहे, रोशनी बेहतर बनी रहे इसके लिए समय-समय पर पलकों को झपकाते रहना जरूरी है, पर ज्यादा लाभ के चक्कर में अनावश्यक रूप से ये काम नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से आप आंखों की रोशनी जल्दी खो सकते हैं। आंखों को स्वस्थ रखने और अंधेपन जैसी समस्याओं से बचाव के लिए आहार में रंग-बिरंगी सब्जियों को शामिल करें साथ ही स्क्रीनटाइम को कम करना भी जरूरी है।

प्रियंका चोपाड़ा के लिए निक ने बनवाई सपनों की हवेली...

लॉस एंजिल्स में 20 मिलियन डॉलर में बनवाया खूबसूरत घर

प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास जल्द ही $20 मिलियन की LA हवेली में वापस जाने के लिए तैयार। तस्वीरों से पता चलता है कि नवीकरण का काम पूरा हो गया है। द सन यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास अपने हाल ही में पुनर्निर्मित लॉस एंजिल्स घर में रहने के लिए तैयार हैं।

प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास जल्द ही $20 मिलियन की LA हवेली में वापस जाने के लिए तैयार। तस्वीरों से पता चलता है कि नवीकरण का काम पूरा हो गया है। द सन यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास अपने हाल ही में पुनर्निर्मित लॉस एंजिल्स घर में रहने के लिए तैयार हैं। पोर्टल ने 20 मिलियन डॉलर की लागत वाली हवेली के ताजा हवाई शॉट्स साझा किए, जिसमें बताया गया कि 'यह मोल्ड द्वारा जोड़े को बाहर निकालने के तीन महीने बाद पुनर्निर्मित दिखता है'। इससे पहले घर से जबरन निकाले जाने के बाद दंपति ने मुकदमा दायर किया था। प्रियंका और निक, जिनकी शादी 2018 में हुई है, हॉलीवुड हिल्स हवेली में बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ रहते हैं, जो जनवरी 2024 में दो साल की हो गईं। नवीनतम हवाई शॉट्स में प्रियंका और निक का घर पूरा होने के करीब दिखता है।

प्रियंका के घर का मामला क्या था?

पेज सिक्स की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका और निक को अपने एलए घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वहां फफूंद का संक्रमण फैल गया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में राजस्थान में अपनी भव्य शादी के कुछ महीनों बाद 2019 में घर खरीदा था - इससे ठीक पहले कि यह 'वस्तुतः रहने लायक नहीं' हो गया।

पोर्टल ने बताया कि निक और प्रियंका की भव्य लॉस एंजिल्स हवेली में पानी की क्षति के कारण फफूंद फैल गई, जिससे कानूनी लड़ाई छिड़ गई जो मई 2023 से चल रही है। पेज सिक्स द्वारा विशेष रूप से प्राप्त मुकदमे की एक प्रति के अनुसार, पूल और स्पा शुरू हो गए अप्रैल 2020 के आसपास प्रियंका और निक के लिए मुद्दों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करें, जिसमें 'छिद्रपूर्ण वॉटरप्रूफिंग' भी शामिल है जो 'फफूंद संदूषण और संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देती है'।

उनकी शिकायत में कहा गया है कि लगभग उसी समय, कथित तौर पर डेक पर बारबेक्यू क्षेत्र में पानी का रिसाव दिखाई दिया और इस रिसाव ने 'डेक के ठीक नीचे आंतरिक रहने वाले क्षेत्र के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया।' घर की समस्याओं ने कथित तौर पर परिसर को 'वस्तुतः रहने योग्य नहीं' और 'स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खतरनाक' बना दिया।

प्रियंका और निक के एलए स्थित घर के बारे में अधिक जानकारी

कथित तौर पर दंपति की एलए हवेली में सात शयनकक्ष, नौ स्नानघर, एक शेफ की रसोई, एक तापमान नियंत्रित वाइन रूम, एक इनडोर बास्केटबॉल कोर्ट, एक आंतरिक बॉलिंग गली, एक होम थिएटर, एक मनोरंजन लाउंज, स्टीम शॉवर के साथ एक स्पा, एक पूर्ण सुविधा है। सर्विस जिम और एक बिलियर्ड्स रूम।

क्रू की सफलता पर बोलीं कृति

निर्माताओं को महिला प्रधान फिल्मों पर भी पैसा लगाने की जरूरत है

भारतीय सिनेमा में महिलाएं और उनकी कहानियां हमेशा असुरक्षित रही हैं, लेकिन कुछ अभिनेत्रियां और निर्माता अक्सर इस धारणा से परे जाकर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। करीना कपूर , कृति सेनन और तब्बू की फिल्म 'क्रू' इसका एक उदाहरण है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है। अब हाल ही में, एक साक्षात्कार में कृति ने कहा है कि फिल्म के निर्देशकों को अब महिला प्रधान फिल्मों पर भी अच्छा खासा निवेश करने की जरूरत है।

कृति ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा, "दर्शकों को थिएटर तक खींचने के लिए एक फिल्म का में किसी हीरो का रोल होना बहुत जरूरी नहीं है। काफी लंबे समय से, लोगों ने पुरुष-केंद्रित फिल्मों की तरह महिला प्रधान फिल्मों को अपनाने का जोखिम नहीं उठाया है। उन्हें लगता है कि दर्शक थिएटर नहीं आएंगे और उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि, अब समय बदल गया है और लोगों की सोच भी काफी बदल गई है।''

अभिनेत्री 'क्रू' की उपलब्धि को हिंदी सिनेमा के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखती है। फिल्म 'क्रू' की सफलता पर बात करते हुए कृति ने कहा 'यह एक तरह की शुरुआत है। मैं कम से कम एक बदलाव की उम्मीद कर रही हूं। लोगों को ऐसी फिल्मों से बहुत उम्मीदें नहीं हैं। लोगों का विश्वास कम है। चीजों को बदलने के लिए उस विश्वास को मजबूत होने की जरूरत है। यदि आप एक फिल्म में उतना ही निवेश करते हैं जो आप डंकी पर करते हैं तो जाहिर है कि महिला प्रधान फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी।'

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित आलिया भट्ट की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' 2022 की हिट के बारे में बात करते हुए कृति ने कहा कि यह फिल्म भी एक महिला केंद्रित फिल्म थी, लेकिन आज भी लोग इस फिल्म को देखना काफी पसंद करते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता का परचम लहराया था।

शिखर पहाड़िया को डेट कर रही हैं जान्हवी

बॉलीवुड दिवा जान्हवी कपूर को मंगलवार को अजय देवगन-स्टारर मैदान की स्पेशल स्क्रीनिंग में देखा गया। वह अक्सर अपने बोल्ड आउटफिट्स और मेंटेन फिगर के लिए खबरों में रहती हैं लेकिन इस बार उनके कस्टमाइज्ड नेकलेस ने लोगों का ध्यान खींचा। बॉलीवुड दिवा जान्हवी कपूर को मंगलवार को अजय देवगन-स्टारर मैदान की स्पेशल स्क्रीनिंग में देखा गया। वह अक्सर अपने बोल्ड आउटफिट्स और मेंटेन फिगर के लिए खबरों में रहती हैं लेकिन इस बार उनके कस्टमाइज्ड नेकलेस ने लोगों का ध्यान खींचा। इस कार्यक्रम के लिए, उन्होंने एक सफ़ेद पैंट-सूट पहना था, लेकिन यह उनका हार था जिस पर उनके कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का नाम 'शिखू' लिखा हुआ था, जो सुर्खियाँ बटोर रहा है। इवेंट में जान्हवी को अपने पिता बोनी कपूर, जिन्होंने मैदान का निर्माण किया था, और अभिनेता-भाई अर्जुन कपूर के साथ पोज़ देते देखा गया। पापाराज़ो वरिंदर चावला ने इवेंट से जान्हवी की एक तस्वीर साझा की, जिसमें उनके नेकलेस की एक ज़ूम क्लिक भी शामिल है। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, ''जान्हवी कपूर ने मैदान की स्क्रीनिंग में अपने कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का 'शिकू' नेकलेस दिखाया।

कौन हैं शिखर पहाड़िया?

शिखर पहाड़िया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के पोते हैं। शिखर और जान्हवी दोनों को अक्सर एक-दूसरे के साथ घूमते हुए देखा जाता है। इतना ही नहीं, जान्हवी हाल ही में शिखर और ओरी के साथ तिरुमाला मंदिर गईं, जहां एक्ट्रेस को पारंपरिक पोशाक पहने देखा गया। कॉफ़ी विद करण के नवीनतम सीज़न में, जान्हवी ने उन तीन नामों के बारे में बात की जो हमेशा उनके स्पीड डायल पर रहते हैं। जवाब में उसने कहा, ''पापा, खुशू और शिकू।'' हालांकि, नाम बताने के तुरंत बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से शिखर का नाम ले लिया है।

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

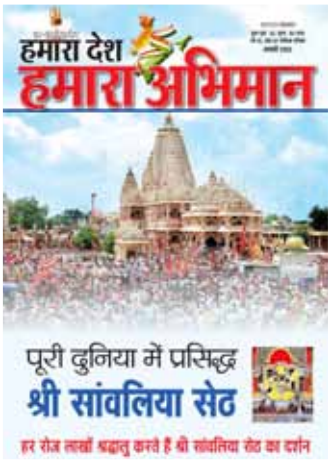

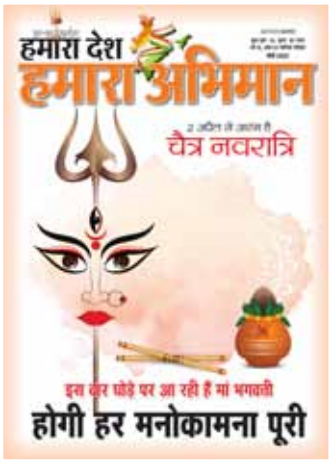

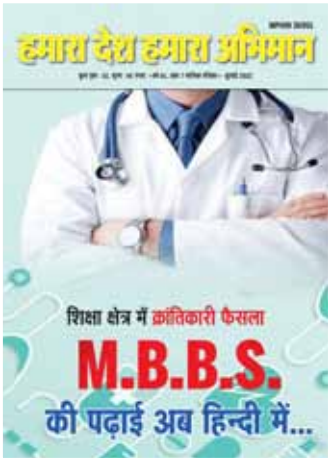

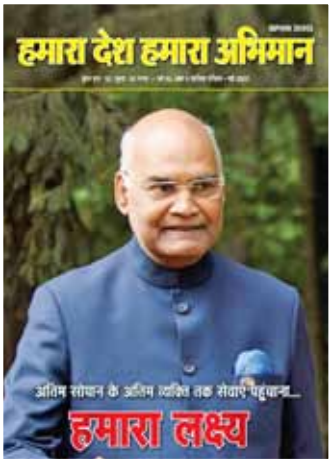

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136

जटा टवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेऽव लम्ब्यलम्बितां भुजंगतुंग मालिकाम्।
डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥1॥

अर्थ : उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है, और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है, और डमरू से डमट् डमट् डमट् की ध्वनि निकल रही है, भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें।